



संक्षिप्तवार्ता

छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका

बिलासपुर। वर्ष 2006 की सुबेदार, प्लाटन कमांडर और उपनिरीक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद भी नहीं सुलझा। एलसी कोसले व अन्य की विशेष अनुमति याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2026 को खारिज कर दिया। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्रीतंद्रशेखर की पीठ के आदेश के साथ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का 23 जुलाई 2026 का फैसला बरकरार रहा।

पुलिस मुख्यालय ने 18 सितंबर 2006 को सुबेदार, प्लाटन कमांडर और उपनिरीक्षक के 380 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। एलसी कोसले, रवि सिंह ठाकुर, विनोद तोड़े और सेयद अहसान अली का चयन आठ अप्रैल 2008 की पहली मेरिट सूची में हुआ। नियुक्ति के बाद उन्होंने प्रशिक्षण पूरा किया। बाद में मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्र-2 में आठ प्रश्नों और उनके माडल उत्तरों में त्रुटियां सामने आईं।

भारत ने पाकिस्तान को हराकर पुरुष हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया

नगोया। भारतीय टीम ने एशियाई खेलों के पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को रोमांचक सेमीफाइन मुकाबले में 4-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है।



अंतिम क्षणों में अभिषेक ने गोल दागकर भारतीय टीम को जीत दिलायी। मैच में 59 मिनट तक स्कोर 3-3 की बराबरी पर था पर 60वें मिनट में अभिषेक ने गोल कर भारतीय टीम को 4-3 से जीत के साथ ही खिताबी मुकाबल में पहुंच दिया। वहीं पाक टीम बाहर हो गयी। भारतीय टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। पहले क्वार्टर में ही भारतीय टीम को 2-0 की बढ़त मिल गयी। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल दागे। हरमनप्रीत ने 5वें मिनट पर पहला गोल और 13वें मिनट पर दूसरा गोल किया। इसके बाद पाकिस्तान ने भी पलटवार करते हुए दूसरे हाफ में एक गोल कर दिया। जिसका जवाब भारतीय टीम ने भी एक गोल कर दिया। भारत के लिए ये तीसरा गोल सुखजीत सिंह ने 23वें मिनट पर गोल किया। वहीं पाकिस्तान के लिए 30वें मिनट में अबू मोहम्मद ने पहला गोल दामा। इस प्रकार दो क्वार्टर के बाद भारत की बढ़त 3-1 हो गयी।

इंडिया गठबंधन में दिखी सोनिया-ममता की दोस्ती, सुप्रिया सुले साथ आई नजर

नई दिल्ली। इंडिया गठबंधन की नई दिल्ली में हुई बैठक में पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी और कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के बीच नजदीकी देखने को मिली। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी को इस बैठक में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी ने ही जोर देकर मनाया था और उनसे मार्गदर्शन देने का आग्रह किया था। बैठक में दोनों नेता साथ बैठी नजर आईं, उनके पास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की सांसद सुप्रिया सुले भी थीं। यह पहली बार नहीं है, जून में हुई पिछली बैठक में भी दोनों नेता गले मिलते हुए दिखी थीं, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई थीं।

थलौट में बनेगी हिमाचल की पहली 500 मीटर लंबी बॉक्स टनल

200 करोड़ होंगे खर्च, एक साल में कार्य को पूरा करने का लक्ष्य



टनल की प्रपोजल बनाया और केंद्र से इसकी मंजूरी मिलने के बाद अब कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि

मंडी। कीरतपुर-मनाली फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत मंडी जिले के थलौट में हिमाचल प्रदेश की पहली बॉक्स टनल बनाई जा रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी (एनएचआई) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि थलौट और डंड कवर के पास फोरलेन को कट एंड कवर के जरिए गुजारा गया था। थलौट बाजार में एक और ओट बाजार में दो कट एंड कवर बनाए गए थे। यह कट एंड कवर भी बॉक्स टनल की तरह ही होते हैं लेकिन बॉक्स टनल की शोप स्क्वेयर में होती है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की आपदा में थलौट बाजार का कट एंड कवर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद एनएचआई ने यहां पर बॉक्स

200 करोड़ की लागत से बने वाली 500 मीटर लंबी बॉक्स टनल के कार्य को एक साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह आर्टिफिशियल टनल होगी जिसे ब्लॉक्स के जरिए बनाया जाएगा। कुल्लू-मनाली की तरफ जाने वाले सारे ट्रैफिक को यहीं से भेजा जाएगा जबकि आने वाला ट्रैफिक ओट की पुरानी टनल से होकर आएगा। जब यह बॉक्स टनल बन जाएगी तो उसके बाद औट में बनाई गई नई टनल भी शुरू हो पाएगी। 2023 की आपदा में कट एंड कवर को नुकसान के साथ ही साथ लगते कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा था। एनएचआई ने सारे नुकसान का आंकलन करके प्रभावितों के लिए 20 करोड़ की राशि

मंजूर की है जिसमें से 12 करोड़ की राशि एसडीएम बालीचौकी के पास जमा करवा दी गई है।

...और कम समय लगेगा

बता दें हिमाचल प्रदेश में कीरतपुर से मनाली के बीच फोरलेन बन रहा है। इसमें कीरतपुर से मनाली के बीच में कुछ हिस्सों का काम होना बाकी है और बन चुके फोरलेन पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। पहले जहां चंडीगढ़ से मनाली पहुंचने में 8-9 घंटे लगते थे, लेकिन अब 4-5 घंटे में मनाली पहुंच जाते हैं। यदि फोरलेन के बचे हुए हिस्सों का भी निर्माण पूरा हो गया तो मनाली के लिए और कम समय लगेगा।

अमित शाह का 23 घंटे का भोपाल दौरा: 35 हजार गोपालकों से करेंगे संवाद

भोपाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करीब 23 घंटे के प्रवास पर भोपाल आ रहे हैं। 12 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे भोपाल पहुंचने के बाद वे होटल ताज में रात्रि विभाग करेंगे। अगले दिन, 3 अक्टूबर को वे गृह, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी और उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दिनभर व्यस्त कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद वे रात 8 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अपने दौरे के मुख्य कार्यक्रम के तहत केंद्रीय गृह मंत्री भेल दशहरा मैदान में आयोजित 'राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन' में शामिल होंगे। इसमें प्रदेशभर से 35 हजार से अधिक गोपालक और दुग्ध सहकारिता समितियों के सदस्य हिस्सा लेंगे। बोनस व सहायता राशि का वितरण : सम्मेलन में पशुपालकों को बोनस राशि, गौशालाओं के लिए सहायता अनुदान और उत्कृष्ट कार्य करने वाली 'गोपालक दीर्घियों' का सम्मान किया जाएगा। विभागीय प्रस्तुतियां : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में 'कृषक कल्याण वर्ष' और 'बलराम कृषि महोत्सव' की उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।

यूपीएससी के शताब्दी समारोह में बोले पीएम मोदी

आयोग पर आज भी कायम है लोगों का भरोसा



सरदार पटेल के योगदान को किया याद

पीएम मोदी ने स्वतंत्रता के बाद प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माण में सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद चुनौती केवल देश को स्वतंत्र बनाए रखने की नहीं, बल्कि उसे प्रभावी ढंग से संचालित करने की भी थी। राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

में योगदान देने वाली पीढ़ियों को शुभकामनाएं दीं।

बारिश कम होने से कई राज्य गंभीर सूखे की चपेट में, सितंबर तक 868.6 मिमी हुई

यह आजादी के बाद से अब तक के 10 सबसे सूखे मानसून सत्रों में शामिल



नई दिल्ली। मानसून में बारिश कम होने से देश के कई राज्य गंभीर सूखे की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि इस साल भारत ने वर्ष 2001 के बाद से अब तक का चौथा सबसे कमजोर दक्षिण-पश्चिम मानसून दर्ज किया है। सामान्य तौर पर जून से सितंबर तक मानसून सत्र के दौरान देश में 868.6 मिलीमीटर औसत बारिश होती है, लेकिन इस बार भारत में केवल 759.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि दीर्घकालिक औसत का 87.4 फीसदी ही है। इस साल कम बारिश का कारण प्रशांत महासागर में तेजी से उभरे मजबूत अल नोर्नो के

प्रभाव को माना जा रहा है।

मौसम विभाग के मुताबिक इस बार देश में राष्ट्रीय स्तर पर मानसून की बारिश में भारी गिरावट दर्ज की गई। 2015 के बाद से पिछले 11 सालों का सबसे सूखा मानसून रहा है। इसके साथ ही यह आजादी के बाद से अब तक के 10 सबसे सूखे मानसून सत्रों में भी शामिल है। देश के कुल जिलों में से करीब 43 फीसदी जिलों में सामान्य से काफी कम या बहुत कम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक जहां मध्य भारत और उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य बारिश हुई। वहीं पूर्वोत्तर और

दक्षिण भारत जल संकट की स्थिति में आ गए। 1901 के बाद से यानी पिछले 125 सालों के इतिहास में पूर्वोत्तर भारत में इस बार सबसे कम बारिश हुई। यहां सामान्य 1,347.4 मिमी की तुलना में केवल 1,014.7 मिमी बारिश दर्ज की गई।

वापसी तेजी से आगे बढ़ी

राज्य में लगातार 5वें साल सूखे का सामना करना पड़ा है। बिहार के कुल 38 जिलों में से 31 जिलों में बारिश की भारी कमी दर्ज की गई है। दक्षिण भारत में पिछले 24 सालों का सबसे सूखा मानसून रहा, जहां सामान्य से 23फीसदी से ज्यादा की कमी दर्ज की गई औसत केवल 542 मिमी बारिश दर्ज हुई। यह 1901 के बाद से चौथी सबसे कम मानसूनी बारिश है। पंजाब में पिछले साल के मुकाबले स्थिति खराब रही, जहां पिछले साल 41फीसदी ज्यादा बारिश हुई थी, वहीं इस साल 42फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई। पिछले 8 सालों में पहली बार पश्चिमी राजस्थान की बारिश में 31फीसदी की गिरावट आई, जो 2009 के बाद सबसे कम है। कुछ क्षेत्रों में कम दबाव के क्षेत्र बनने से हल्की से मध्यम बारिश हुई, लेकिन समग्र रूप से सितंबर में बारिश सामान्य से कम रही। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्से सूखे जैसे संकट से प्रभावित रहे, जबकि उत्तर-पश्चिम भारत में मानसून की वापसी तेजी से आगे बढ़ी।

सीएम विजय ने पीएमके को सरकार में दो कैबिनेट पद देने का दिया प्रस्ताव

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़े सियासी बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। सीएम सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलनागा वेन्ना कडगम (टीवीके) और पट्टाली मक्कल कच्चम (पीएमके) के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक विजय ने पीएमके को अपनी सरकार में दो कैबिनेट पद देने का प्रस्ताव दिया है। इस संभावित गठजोड़ में सबसे बड़ा पेंच पीएमके के बीजेपी के साथ मौजूदा संबंधों का है, जिसे औपचारिक फैसले

से पहले तोड़ना पड़ सकता है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों दलों के बीच बातचीत पीएमके नेता अनुबुमणि रामदास और सीएम विजय थलपति के राजनीतिक सलाहकार जॉन अरोकीआसामी के जरिए से हो रही है। अरोकीआसामी 2016 के विधानसभा चुनाव में भी पीएमके की राजनीतिक रणनीति पर काम कर चुके हैं। पीएमके का आगामी 6 अक्टूबर को होने वाले मद्रुरतकम और धरापुरम उपचुनाव में तटस्थ रहने का फैसला भी इस बड़ी



राजनीतिक बातचीत का हिस्सा माना जा रहा है।

2026 के विधानसभा चुनाव में

सीधे विजय की ओर जाते जाता दिख रहा है

हालांकि, पीएमके को गठबंधन में शामिल करना आसान नहीं होगा। टीवीके के एक अन्य सहयोगी दल विदुथलाई चिक्थैयल काची (वीसीके) और पीएमके के बीच ऐतिहासिक टकराव रहा है, जिससे गठबंधन के भीतर चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। इसके बावजूद टीवीके नेताओं का मानना है कि वीसीके के लिए विजय का साथ छोड़ना मुश्किल होगा क्योंकि दलित मतदाताओं के एक बड़े हिस्से का समर्थन सीधे विजय की ओर जाता दिख रहा है।

पीएमके ने एआईएडीएमके-बीजेपी गठबंधन के साथ लड़ा था और चार सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन

अब उसका तटस्थ रख टीवीके के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। टीवीके सूत्रों के हवाले से बताया गया है

कि प्रस्ताव में अनुबुमणि रामदास की पत्र 'और पीएमके की फ्लोर लीड सीन्या अनुबुमणि को एक कैबिनेट पद मिल सकता है, जबकि दूसरा पद पीएमके विधायक ए गणेश कुमार को दिए जाने की चर्चा है।

कम्युनिस्ट पार्टियां भी पीएमके के आने से टीवीके से दूरी बना सकती हैं, जैसा कि उपचुनावों में उनके स्वतंत्र लड़ने से दिख रहा है। सबसे बड़ी चुनौती पीएमके के लिए बीजेपी के साथ अपने रिश्ते को तोड़ना है।

पीएम मोदी ने कैप्टन मच्छर को कहा हीरो, बोले- भारत को तुम पर गर्व

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लाईवुड की भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी की जमकर तारीफ की है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, कैप्टन मच्छर ने दुर्घटना से तेल अवीव जा रहे एक विमान में सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प दिखाया। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी ने एक बड़ी त्रासदी को टालने में मदद की, जिसके लिए भारत को उन पर गर्व है। यह घटना 30 सितंबर को प्लाईवुड की फ्लाइट एफजेड 1073 में हुई, जिसमें 170 से अधिक लोग सवार थे। उड़ान के दौरान, कॉकपिट में को-पायलट ने कैप्टन मच्छर पर अचानक चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए और इसी दौरान विमान ने तेजी से ऊंचाई खोनी शुरू कर दी, कुछ ही समय में करीब 14 हजार फीट नीचे आ गया। इस से यात्रियों में अफरातफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, कैप्टन स्मित मच्छर ने हमलावर का विरोध किया और कॉकपिट का दरवाजा खोलने में मदद की। इससे यात्रियों और क्रू के कुछ सदस्यों को कॉकपिट तक पहुंचने और हमलावर को काबू करने का मौका मिला। विमान में यात्रा कर रहे कुछ ऑफ-ड्यूटी पायलटों ने भी विमान को संभालने में मदद की, जिसके बाद प्लाइट को सऊदी अरब के तबूक एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा गया और वहां सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी मच्छर को सच्चा हीरो बताया है।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किया उल्लेख

समारोह के दौरान एक स्मारकीय डाक टिकट भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने यूपीएससी की प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी जानकारी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1920 में सुभाष चंद्र बोस भी इसी चयन प्रक्रिया से गुजरे थे। उस समय ब्रिटिश शासन होने के बावजूद

परीक्षा में संस्कृत का प्रश्नपत्र भी होता था और सुभाष चंद्र बोस ने संस्कृत में परीक्षा दी थी।

देश पहले, नागरिक पहले हो चयन की कसौटी

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज चयनित होकर सार्वजनिक सेवा में आने वाले युवा विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया में दो कसौटियां हमेशा

ध्यान में रखी जानी चाहिए- देश पहले और नागरिक पहले।

पीएम मोदी ने कहा कि सार्वजनिक सेवा में ऐसे युवाओं को आना चाहिए जो केवल सरकारी पद से आकर्षित न हों, बल्कि लोगों की सेवा की भावना से प्रेरित हों। भर्ती परीक्षा में उम्मीदवार के ज्ञान के साथ यह भी समझने का प्रयास होना चाहिए कि वह सिविल सेवा में क्यों आना चाहता है।

टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से झटका

804 करोड़ वाले चार बैंक खातों को चलाने की मांग खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को बैंक खातों के मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.वी. वराले की पीठ ने पार्टी के चार डेबिट-फ्रोज बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति देने वाली याचिका खारिज कर दी। इन खातों में करीब 804 करोड़ रुपये होने की बात कही गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से भी इनकार किया, जिसमें खातों को संचालित करने की मांग ठुकराई गई थी। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल मामले के गुण-दोष में नहीं जाना चाहती। अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट से संबंधित मामले की सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध किया।

मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मनी लॉन्ड्रिंग जांच से



जुड़ा है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी के कुछ फ्रोज खातों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध बरकरार रखते हुए पार्टी को रोजमर्रा के खर्चों के लिए सीमित राहत दी थी।

ईडी की जांच में पार्टी के बैंक खातों में जमा धन और कथित वित्तीय अनियमितताओं की पड़ताल की जा रही है। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने भी खातों से पार्टी के दैनिक खर्चों के लिए कुछ राशि उपलब्ध कराने की संभावना पर ईडी से जवाब मांगा था। ताजा आदेश के बाद अब खातों से जुड़ा मुख्य विवाद कलकत्ता हाईकोर्ट में ही आगे चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया है।

संपादकीय फॉर्म 6 का फ़ॉइ

चुनाव आयोग, खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार गुप्ता, विपक्षी आंदोलन और राजनीति के निशाने पर हैं। कांग्रेस कार्यसमिति और शेष विपक्ष की सामूहिक मांग है कि विशेष गहनपुनरीक्षण (एसआईआर) को निलंबित किया जाए। यदि संभव है, तो उसे रद्द ही कर दिया जाए। अभी तक जिन 13.३7 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उन्हें बहाल किया जाए। 1इह कैसे संभव है, क्योंकि उनमें से 2.80 करोड़ से ज्यादा मतदाता तो दिवंगत (मृत) हो चुके हैं। शेष 10.57 करोड़ काटे गए नामों पर चुनाव आयोग को बाध्य किया जाना चाहिए। दिल्ली में यह मामला सामने आया है। बेला एस्टेट में अधिकतर झुग्गी-झोंपड़ियां थीं। लोगों ने अवैध अतिक्रमण किए हुए थे और वे वहां बसे हुए थे। 10222–23 में उन झुग्गियों को तोड़ दिया गया। वहां 728 वैध मतदाता रहते थे, जिनके पास चुनाव आयोग की मान्यता थी और वे लगातार मतदान करते रहे थे। झुगियां टूटीं, तो वे बेघर हो गए। एसआईआर अभियान के तहत बीएलओ को उस जगह कोई नहीं मिला। किसी एक ने मतदाता पहचान पत्र दिखाया। नतीजतन 728 में से 727 मतदाताओं के नाम काट दिए गए।ता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उन बेघरों के पास गए और मोबाइल पर ईआरओ से पूछा कि इतने नाम किस आधार पर काट दिए गए? बहरहाल जब यह खबर टीवी चैनलों और अखबारों की सुर्खियों में आ गई कि बेला एस्टेट के बेघर परिवार फ्लाईओवर के नीचे जीने को विवश हैं, तो चुनाव आयोग ने अपने बीएलओ भी भेज भेजे। कटे हुए नामों के उन लोगों को फॉर्म 6 भर कर नया मतदाता बनने की सलाह दी गई। खबर बताई जाती है कि 418 लोगों से फॉर्म 6 भरवा भी लिए गए हैं। अब नई मतदाता–सूची में उनके नाम भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने यह संवैधानिक फ़ाँड खेला है। फॉर्म 6 उन लोगों के लिए है, जो बिल्कुल पहली बार मतदाता बनना चाहते हैं। वे पहले कभी भी मतदाता न रहे हों। ऐसा घोषणा–पत्र भी भर कर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। लेकिन ये तो पहले भी मतदाता रहे हैं और उन्होंने एसआईआर में अधिकृत फॉर्म भी भर था। क्या यह संवैधानिक कवायद है? यदि 418 काटे गए नाम, अंततः, मतदाता बन जाते हैं, तो शेष लोग भी मतदाता बनाए जा सकते हैं।

तो फिर एसआईआर का औचित्य क्या रहा? क्या इस तरह चुनाव आयोग फ़ाँड नहीं कर रहा है और फॉर्म 6 के साथ झूठे घोषणा पत्र भी नहीं भरवा रहा है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जानकारी में यह पूरा मामला है, लिहाजा उनका आंदोलन सीईसी ज्ञानेश कुमार गुप्ता के इस्तीफे पर केंद्रित है। राहुल को यकीन है कि अंततः प्रधानमंत्री मोदी ही सीईसी का इस्तीफा करवाएंगे, क्योंकि ज्ञानेश तो उनकी की कठपुतली हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो प्रधानमंत्री का ही इस्तीफा मांग लिया है। फॉर्म 6 के इस कथित फजीवाड़े में भाजपा के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी फंसे हैं। वह जब राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो वह पंजाब के मतदाता थे और आप के प्रत्याशी थे, लेकिन बाद में आप के 7 राज्यसभा सांसद पालाबदल कर भाजपा में शामिल हो गए, तो अब उन्हें दिल्ली का मतदाता बनाया गया है। इसमें कोई अपराध नहीं है, क्योंकि व्यक्ति स्थानांतरित होता है, तो मतदाता भी बदला जा सकता है। जबतता संवैधानिक हेराफेरी न की जाए। बताया जाता है कि राघव चड्ढा से फॉर्म 6 भरवाया गया है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन आप ऐसा कह रही हैं और अदालत में इसे चुनौती देने की बात भी पाटीं ने की है। दरअसल एसआईआर का मुद्दा बेवैद पीछा हो गया है। दिल्ली में ही 9 लाख से अधिक बांग्लादेशी बस चुके हैं। वे अभी तक मतदाता भी बने रहे हैं। सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने उन्हें एसआईआर के दौरान क्या चिह्नित किया है? सर्वोच्च अदालत में यह मामला विचाराधीन है और एक मामले में तो एसआईआर को अवैध करार देने की भी मांग की गई है। जो भी हथ्र होगा, देखा जाएगा, लेकिन इस मुद्दे ने हमारी राजनीति को बिल्कुल विभाजित और विषाक्त बना दिया है। विपक्ष को चुनाव आयोग की मनमानियां पसंद नहीं हैं और सारा देश इस मसले पर अलोकित है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्ताव भी लेकर आ रहा है। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग के जरिए हटाना आसान नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास वांछित बहुमत नहीं है, फिर भी इसके जरिए चुनाव आयोग के खिलाफ एक तरह का माहौल तो बन ही रहा है।

भारत की ऊर्जा यात्रा अब केवल बिजली उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रह गई है,बल्कि देश ऐसी ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन, उसका भंडारण और देश के विभिन्न हिस्सों तक निर्बाध संचरण एक साथ मजबूत हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण- क्कक योजना को मंजूरी इसी व्यापक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।	
---	--

आलेख

1990-199६ के दौर में भारत के 10 वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे टी. एन. शेपन। इनकी छवि भारतीय इतिहास में एक निडर, कड़क और क्रांतिकारी सुचारक की थी। शेपन ने भारतीय चुनाव प्रणाली की पूरी सूरत बदल दी और राजनेताओं के मन में कानून का खौफ पैदा किया। उनके दौर में एक कहावत प्रचलित थी कि नेता केवल दो ही लोगों से डरते हैं। एक तो ईश्वर से दूसरे टी.एन. शेपन से। शेपन ने संविधान के अनुच्छेद 324 की ताकत को पहचाना और साबित किया कि चुनाव आयोग भारत सरकार का नहीं, बल्कि भारत का होता है। उन्होंने आयोग को एक पूर्णतः स्वतंत्र और शक्तिशाली स्वायत्त निकाय बनाया और आदर्श आचार संहिता को कड़ाई से लागू कराते हुये कई प्रभावशाली मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों तक पर रोख लगा दी और कई दंड दिए।शेपन ने बृथ कैप्चरिंग, जाली वोटिंग, दीवारों पर जबरन पोस्टर चिपकाना आदि लाउडस्पीकों का ब्रैचइक इस्तेमाल आदि पर सब्जी से प्रतिबंध लगाया। उन्होंने चुनाव प्रचार के खर्च की सीमा तय की और उसका हिसाब मांगना शुरू किया। शेपन ने ही चुनावों में सरकारी

गाड़ियों, बंगलों और मशीनरी के दुरुपयोग पर पूरी तरह रोक लगाई। वे किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुके। और चुनावी भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके इसी महाअभियान के लिए उन्हें 199६ में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

परन्तु दुःखद है कि वही चुनाव आयोग आज के दौर का सबसे निकृष्ट,भ्रष्ट और सत्ता के चापलूस व कठपुतली आयोग के रूप में देश व दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की सप्रमाण दर्जनों शिकायत के बावजूद आयोग के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। असली मतदाताओं के नाम काटे जाने व फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़ने की अनगिनत शिकायतें होती रहती हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गाँधी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी, फर्जी मतदान और वोट चोरी के आरोपों को लेकर तीन बार पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिया और ठोस दस्तावेजों के साथ देश के सभसे सबूत पेश किए। परन्तु हर बार एक तरफ तो चुनाव दवा केन्द्रों के सचिव देश के सभसे प्रबुत पेश किए। परन्तु हर बार एक तरफ तो चुनाव आयोग द्वारा या तो आरोपों से इंकार किया गया या लीपापोती करने वाले जवाब दिए

चुनाव आयोग, एसआईआर और फॉर्म 6: सवाल अब सुप्रीम कोर्ट तक

चुनाव सिर्फ मतदान के दिन की कुछ घंटों की प्रक्रिया नहीं है। उसके पीछे महीनों चलने वाली एक पूरी व्यवस्था होती है—मतदाता सूची तैयार करने से लेकर नाम जोड़ने और हटाने तक, दावों–आपत्तियों से लेकर अंतिम सूची जारी होने तक। इस पूरी प्रक्रिया में एक आम मतदाता सबसे ज्यादा जिस चीज पर भरोसा करता है, वह है चुनाव आयोग। लेकिन जब उसी आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे, उसके फैसलों को लेकर राजनीतिक दल आमने–सामने हों और आयोग के भीतर की कार्यप्रणाली भी सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनने लगे, तब मामला सिर्फ राजनीति का नहीं रह जाता। फिर सवाल भरोसे का होता है।

अभी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर यही हो रहा है। विपक्ष चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठा रहा है। प्रदर्शन हो रहे हैं। भाजपा और केंद्र सरकार विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहे हैं और चुनाव आयोग के बचाव में भी सामने आ रहे हैं। यहीं से एक अहम सवाल पैदा होता है—जब सवाल चुनाव आयोग से हैं, तो उसके बचाव की राजनीतिक जिम्मेदारी सरकार क्यों उठा रही है? क्या बेहतर रास्ता यह नहीं होगा कि चुनाव आयोग खुद हर सवाल का तथ्य और दस्तावेज के साथ जवाब दे और सरकार यह सुनिश्चित करे कि पूरी प्रक्रिया इतनी पारदर्शी हो कि किसी को उसकी निष्पक्षता पर संदेह करने का मौका ही न मिले? क्योंकि चुनाव आयोग किसी सरकार का विभाग नहीं है। वह एक संवैधानिक संस्था है। उसकी विश्वसनीयता सत्ता के समर्थन से नहीं, उसकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता और पारदर्शी कार्यप्रणाली से बनती है। इसलिए इस पूरे विवाद को केवल भाजपा बनाम विपक्ष के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। एसआईआर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ मतदाता सूची के पुनरीक्षण तक सीमित नहीं रहा। इसके साथ चुनाव आयोग के फैसले लेने की प्रक्रिया, आयोग के भीतर मतभेद और कुछ प्रशासनिक फैसले भी चर्चा में आ गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। चुनाव आयोग दूसरी तरफ कहता रहा है कि मतदाता सूची को अद्यतन रखना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है और पात्र मतदाताओं के अधिकारी की रक्षा के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं मौजूद हैं। इन दोनों दवों के बीच असली सवाल यह है कि प्रक्रिया जमीन पर कितनी पारदर्शी और नागरिक के लिए कितनी सुरक्षित है। किसी मतदाता का नाम सूची से हटना कोई सामान्य प्रशासनिक घटना नहीं है। उसके पीछे मतदान का अधिकार जुड़ा है। इसलिए नाम हटाने का कारण स्पष्ट होना चाहिए, संबंधित व्यक्ति को जानकारी मिलनी चाहिए और आपत्ति तथा अपील का पर्याप्त अवसर होना चाहिए। इस विवाद को और गंभीर बनाने वाली बात चुनाव आयोग के भीतर कश्चित असहमतियों की खबरें हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी ने पिछले दस महीनों में आयोग के कुछ फैसलों पर 14 बार आपत्ति दर्ज की। रिपोर्ट में एसआईआर और उससे जुड़े कई फैसलों का उल्लेख किया गया। दूसरी ओर

दवाओं और इलाज में लूट—खुलेआम कल्लेआम

स्वास्थ्य सेवा किसी भी सभ्य समाज की सबसे बड़ी मानवीय जिम्मेदारी है। बीमार व्यक्ति डॉक्टर और अस्पताल के पास केवल इलाज के लिए नहीं जाता, वह अपना जीवन और भरोसा दोनों सौंपता है। इसलिए जब इसी भरोसे को मुनाफे का माध्यम बना दिया जाए तो सवाल केवल महंगे इलाज का नहीं, बल्कि समाज की संवेदनशीलता के संकट का बन जाता है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कैसर की एक दवा का उदाहरण सामने आया, जिसकी कीमत रिटेलर के लिए लगभग 2,700 रुपये थी, लेकिन उसकी एमआरपी 27,000 रुपये तक रखी गई। यानी कीमत में करीब दस गुना अंतर। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति सदीप मेहता की पीठ ने इस पर बेहद गंभीर चिंता जताते हुए इसे मरीजों के साथ दिनदराई लूट और अत्यंत नैके के साथ निपटने का फैसला किया। अदालत ने केंद्र से सभी दवाओं पर समान 16 प्रतिशत मार्जिन की संभावना पर विचार करने को कहा और अस्पतालों की अपनी फार्मेसी से ही दवा खरीदने की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। मामले

की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को है। यह घटना केवल एक दवा की कीमत का मामला नहीं है। इसके पीछे स्वास्थ्य व्यवस्था के उस बड़े संकट को देखना होगा, जिसमें मरीज बीमारी से कम और इलाज के खर्च से अधिक भयभीत होने लगा है। कैसर जैसी बीमारी में परिवार की वर्षों की बचत, जमीन–जायदाद और घर तक बिक जाते हैं। ऐसे समय में यदि अस्पताल, दवा कंपनियां या कोई अन्य व्यवस्था मरीज की मजबूरी को मुनाफे का अवसर समझे तो यह चिकित्सा की आत्मा पर प्रश्नचिह्न है। सरकार का तर्क हो सकता है कि हर ऊंची कीमत के लिए फार्मा कंपनी जिम्मेदार नहीं है। निजी अस्पताल भी कीमत बढ़ाते हैं। जिम्मेदारी एक–दूसरे पर डालने से मरीज को राहत नहीं मिलेगी। सरकार की पहली जिम्मेदारी स्पष्ट और प्रभावी मूल्य नियंत्रण, पारदर्शी बिलिंग और नियमित निगरानी सुनिश्चित करना है। डीपीसी ओ –2013 और पन पीप जी ऐसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं. अदालत में सामने आए ऐसे मामलों से यह प्रश्न उठता है कि नियमन का लाभ वास्तव में मरीज तक पहुंच रहा

है या नहीं। निजी अस्पतालों को भी यह समझना होगा कि अस्पताल उद्योग हो सकता है, लेकिन मरीज कोई ग्राहक मात्र नहीं है। डॉक्टर के सामने बैठा व्यक्ति अपने जीवन के सबसे कमजोर क्षण में होता है। उसे भय दिखाकर अनावश्यक जांच, महंगी दवा, अतिरिक्त प्रक्रिया या अनावश्यक ऑपरेशन की ओर धकेलना चिकित्सा–व्यवस्था के मूल उद्देश्य के विरुद्ध है। हालांकि यह भी उतना ही जरूरी है कि ईमानदारी से सेवा करने वाले लाखों डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को कुछ संस्थानों की गलत प्रथाओं के कारण सामूहिक रूप से दोषी न ठहराया जाए। सबसे चिंताजनक स्थिति तब होती है जब सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का खर्च भी अंततः करदाता की जेब से जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी संदर्भ में सवाल उठाया कि यदि मरीज सरकारी योजना के अंतर्गत उपचार करा रहा है तो महंगी दवाओं की प्रत्युति तं का बोझ आखिर किस पर पड़ेगा—सरकार पर और अंततः जनता पर। मृत्यु के बाद भी अस्पताल का पूरा भुगतान न होने तक शव परिजनों को न सौंपने जैसी शिकायतें इस

व्यवस्था के मानवीय पक्ष पर और बड़ा प्रश्न खड़ा करती हैं। चिकित्सा सेवा में पैसा आवश्यक हो सकता है, लेकिन मनुष्यता उससे बड़ी है। भारत की परंपरा में चिकित्सा को सेवा माना गया। मंदिरों, धर्माथ संस्थाओं और समाजसेवियों ने औषधालय चलाए, गरीबों को मुफ्त दवा दी। आज चिकित्सा विज्ञान ने असाधारण प्रगति की है, लेकिन यदि इलाज इतना महंगा हो जाए कि बीमारी से बचने के बाद परिवार आर्थिक रूप से समाप्त हो जाए, तो विकास की दिशा पर पुनर्विचार जरूरी है। अब सरकार को केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि दवा की कीमत से लेकर अस्पताल के पैकेज, डॉक्टर की फीस, जांच, इम्यूला, फार्मेसी और अंतिम बिल तक पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता लानी होगी। हर मरीज को दूसरी दुकान से दवा खरीदने की स्वतंत्रता, दवा की खरीद कीमत और मरीज से वसूली गई कीमत की स्पष्ट जानकारी तथा अनावश्यक उपचार के विरुद्ध स्वतंत्र शिकायत तंत्र मिलना चाहिए। न्यायपालिका का हस्तक्षेप स्वागतयोग्य है, लेकिन सवाल यह भी है कि अदालतों की टिप्पणियां और आदेश जमीन

पर कितनी तेजी से लागू होते हैं। सरकार और नियामक संस्थाएं यदि समय पर कार्रवाई करें तो हर मामले को न्यायालय तक पहुंचाने की जरूरत ही क्यों पड़े? स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार का अर्थ केवल नए अस्पताल और अत्याधुनिक मशीनें नहीं है। असली विकास तब होगा जब गरीब और मध्यमवर्गीय व्यक्ति बीमारी को आर्थिक विनाश का पर्याय न समझे।

आज जरूरत है कि सरकार, न्यायपालिका, डॉक्टर, अस्पताल, फार्मा उद्योग और समाज—सभी अपनी भूमिका को फिर से समझे। किसी युद्ध में बम और गोलियां मनुष्य को मारती हैं, लेकिन यदि स्वास्थ्य व्यवस्था में लालच हावी हो जाए तो बीमारी के बीच आर्थिक और मानसिक शोषण भी मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है। इसलिए दवाओं और इलाज की लूट को केवल बाजार का विषय नहीं, मानव जीवन और सामाजिक न्याय का प्रश्न मानकर रोकना होगा। वरना वह दिन दूर नहीं जब बीमारी से ज्यादा महंगे इलाज से लाखों लोगों की मौत हो जाएगी।

लेखक— सनत जैन

हरित ऊर्जा की नई राह पर भारत

यह योजना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर इंद्रा–रेट ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के साथ 135 गीगावॉट तक नवीकरणीय ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्षमता विकसित करेगी।भारत में सौर और पवन ऊर्जा की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं देश के अनेक राज्यों में बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित हो रही हैं, लेकिन इस ऊर्जा का वास्तविक लाभ तभी संभव है जब इसे मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क के माध्यम से उन क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके जहां इसकी आवश्यकता है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-कक्कड़की सुनौती का समाधान प्रस्तुत करता है। राज्यों के भीतर ट्रांसमिशन व्यवस्था को सुदृढ़ करने से नवीकरणीय ऊर्जा के ग्रिड एकीकरण और पावर डेक्क्यूेशन को गति मिलेगी तथा स्वच्छ ऊर्जा को बिजली की मुख्यधारा में अधिक प्रभावी ढंग से शामिल किया जा सकेगा।

इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में 50 गीगावॉट–घंटे की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्षमता का प्राधान्य है नवीकरणीय ऊर्जा की सबसे बड़ी चुनौती उसकी प्रकृति से जुड़ी है। सूर्य की रोशनी हर समय उपलब्ध नहीं होती और हवा की गति भी समान नहीं रहती। ऐसे में सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन में उतार–चढ़ाव स्वाभाविक है। बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण इस चुनौती का महत्वपूर्ण समाधान बन सकता है।जब नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन अधिक होगा, तब अतिरिक्त बिजली को संग्रहित किया जा सकेगा और आवश्यकता के समय उसका उपयोग किया जा सकेगा।।इससे ग्रिड में लचीलापन आएगा और बिजली की आपूर्ति को अधिक स्थिर बनाने में मदद मिलेगी।

बीईएसएस की 50 जी डब्लू एव क्षमता केवल ऊर्जा भंडारण का आकड़ा नहीं है, बल्कि यह भारत की बदतीली ऊर्जा व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत का संकेत भी है। पीक आवर में बिजली की बढ़ती मांग, ग्रिड में संभावित कंजेशन और नवीकरणीय ऊर्जा की अनियमित उपलब्धता इसी चुनौतियों से निपटने में यह व्यवस्था उपयोगी होगी। विशेष रूप से उस समय जब सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती, संग्रहीत ऊर्जा मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-कक्कड़की विनियम 2032–33 तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी कुल परियोजना लागत 1,86,405 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इसमें 1,36,378 करोड़ रुपये इंद्रा–रेट ट्रांसमिशन सिस्टम के विकास के लिए और लगभग 50,000 करोड़ रुपये 50 क्कड़ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए निर्धारित हैं। योजना

के अंतर्गत कुल 54,082 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान है। यह सहायता इंद्रा–रेट ट्रांसमिशन शुल्क को कम करने में मदद करेगी, जिसका सीधा संबंध बिजली की लागत से है।।इसका अंतिम लाभ बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचने की संभावना है।इस योजना की कार्यान्वयन व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है।इंद्रा–रेट ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाली ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को टैरिफ आधारित प्रतियस्धी बोली के माध्यम से लागू किया जाएगा।।वैदी ब्राउनफोर्ड अपोइडेशन और नेटवर्क को मजबूत करने से जुड़े कार्य कॉरेंट प्लान बेसिस पर किए जाएंगे।राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज समूह कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भूमिका निभाएंगी,जबकि ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर्स बिल्ड–ओन– ऑपरेट–मेनटेन मॉडल के तहत प्रतियस्धी बोली प्रक्रिया में भाग लेंगे।इससे परियोजनाओं के निर्माण के साथ उनके दीर्घकालिक संचालन और रखरखाव की व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण–कक्कड़ा महत्व केवल बिजली क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसके प्रभाव ऊर्जा, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र तक पहुंचेंगे। बड़े पैमाने पर ट्रांसमिशन नेटवर्क के निर्माण से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के निर्माण और उपयोग

से घरेलू ऊर्जा भंडारण उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा।इसके साथ ही संचालन, रखरखाव और आधुनिक ग्रिड प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक कुशल रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।यह योजना भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा लक्ष्यों से भी जुड़ी हुई है। 2035 तक 900 गीगावॉट स्थापित गैर–जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा।उसके साथ मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क और पर्याप्त ऊर्जा भंडारण क्षमता भी आवश्यक होगी।ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण–कक्कड़न दोनों आवश्यकताओं को एक साथ संबोधित करता है।यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।भारत आज एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहां ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय सुरक्षा को अलग–अलग नहीं देखा जा सकता। बढ़ती अर्थव्यवस्था, तेजी से बढ़ता औद्योगिक उत्पादन, शहरीकरण और डिजिटल अर्थव्यवस्था बिजली की मांग को लगातार बढ़ा रहे हैं।ऐसे में देश को ऐसी ऊर्जा व्यवस्था चाहिए जो पर्याप्त होने के साथ स्वच्छ, विश्वसनीय और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के साथ मजबूत ट्रांसमिशन और ऊर्जा भंडारण इसी दिशा में आधारभूत आवश्यकता बन चुके हैं।ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण–कक्कड़सी बदतीली आवश्यकता के अनुरूप भारत

के ऊर्जा ढाँचे में नई दिशा देता दिखाई देता है। 1३5 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा के संरक्षण की क्षमता, 50 जी डब्लू एव ऊर्जा भंडारण और 1,86,405 करोड़ रुपये का कुल निवेश देश की ऊर्जा संरचना के व्यापक विस्तार का संकेत है। इसका उद्देश्य केवल आज की बिजली जरूरतों को पूरा करना नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिसमें स्वच्छ ऊर्जा देश की आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार बने।ऊर्जा आत्मनिर्भरता, हरित विकास और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में भारत की यात्रा अब उत्पादन से आगे बढ़कर संचरण और भंडारण के चरण में पहुंच रही है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण–कक्कड़ इसी परिवर्तन की महत्वपूर्ण कड़ी है। आने वाले समय में जब देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा मांग दोनों तेजी से विस्तार करेंगी, तब मजबूत ग्रिड, पर्याप्त भंडारण और व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भारत के विकास में नई ऊर्जा रीढ़ बन सकती है।यही दवा आधार है, जिस पर स्वच्छ ऊर्जा से समर्थ, आत्मनिर्भर और पर्यावरण–संतुलित भारत की तस्वीर आकार ले रही है।

लेखक– विनोद सिंह तक्रियावाला (विनोद सिंह तक्रियावाला, स्वतंत्र प्रकाश एवं सम्पाकार)



गये। हैरत की बात तो यह है कि जब जब चुनाव आयोग की नीयत व उसकी कार्यशैली पर उँगली उठती चुनाव आयोग के पक्ष में सत्ता के नेता या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोर्चा संभाल लेते। पिछले दिनों जब राहुल गांधी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी, मैच–फिक्सिंग और देशद्रोही जैसे गंभीर आरोप लगाये गये और उन्हें सरकारी गवाह बनने की सलाह दी गयी, इससे तिलमिलाये भाजपा प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी का राजनीतिक ज्ञान अत्यंत शून्य है और उन्हें भारत की राजनीति का मूलभूत ज्ञान ही नहीं है। भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी में समझ और ज्ञान की कमी

है, वे असलियत को समझ नहीं पाते हैं और उनका विवेक पूरी तरह शून्य है। भाजपा प्रवक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता पाने के लिए छटपटा रही है और अपनी चुनावी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है।

परन्तु इस बार मामला चुनाव आयोग द्वारा चलायी गयी एसआईआर अर्थात विशेष मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में की जा रही घोर धांधली का है और इस प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले केवल राहुल गांधी या विपक्षी दल व नेता ही नहीं बल्कि कई पूर्व चुनाव आयुक्त व नौकरशाह भी हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों और पूर्व केंद्रीय गृह

सचिव व केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा के ही नेता आर.के. सिंह जैसे वरिष्ठ अधिकारियों और अनेक पूर्व संवैधानिक पदाधिकारियों ने भी चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को मनमाना, दोषपूर्ण और कानूनी प्रावधानों के विरुद्ध करार दिया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुर्देशी ने कहा कि वे शुरूआत से ही एसआईआर प्रक्रिया के आलोचक रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल के दौरान चुनाव आयोग के काम करने का तरीका बेहद मनमाना रहा है। इसी तरह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया अनावश्यक है और इसके संचालन में आयोग द्वारा अपनाई गई पूरी कार्यप्रणाली तथा पद्धति दोषपूर्ण है। लवासा ने कहा कि चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर उठा यह विवाद काफी अग्रिय है और इससे लोकतांत्रिक संस्था की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व गृह सचिव आर. के. सिंह ने तो एक खुला पत्र जारी करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर एसआईआर अभियान के दौरान कानून का

करने के पर्याप्त साधन होने चाहिए। सरकार को हर सवाल का राजनीतिक जवाब देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और अगर प्रक्रिया में कहीं कमी है तो उसे स्वीकार करना भी संस्था की कमजोरी नहीं है। इसलिए सरकार से सवाल केवल यह नहीं होना चाहिए कि वह चुनाव आयोग के पक्ष में क्यों बोल रही है। सवाल यह भी होना चाहिए कि वह आयोग को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए क्या कर रही है।

अब यह विवाद न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा भी बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के कामकाज और रकमसे जुड़े सवालों को लेकर याचिकाएं पहुंची हैं। अदालत में जब इन मामलों की सुनवाई होगी तो चुनाव आयोग को अपने फैसलों और प्रक्रियाओं का कानूनी आधार स्पष्ट करना होगा। यदि केंद्र सरकार अदालत में चुनाव आयोग के फैसलों का बचाव करती है, तो यह उसका कानूनी अधिकार है। लेकिन इससे यह सवाल भी उठ सकता है कि सरकार और चुनाव आयोग एक ही तरफ क्यों दिखाई दे रहे हैं। इसका सबसे बेहतर जवाब राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि पारदर्शिता और रिकॉर्ड हो सकते हैं। इस पूरे विवाद को भाजपा बनाम कांग्रेस, सरकार बनाम विपक्ष या मोदी सरकार बनाम चुनाव आयोग के रूप में देखना आसान है। लेकिन असली केंद्र में है मतदाता। वह नागरिक जिसे यह जानना है कि मतदाता सूची में उसका नाम है या नहीं, अगर कोई गलती हुई तो वह उस टीक करा सकता है या नहीं और मतदान के दिन उसकी आवाज व्यवस्था में दर्ज होगी या नहीं।

इसलिए आज सबसे जरूरी सवाल यह नहीं है कि किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा प्रभावी रही। सवाल यह है कि चुनाव आयोग अपने ऊपर उठे सवालों का कितना स्पष्ट जवाब देता है। सरकार से भी सवाल यही है—क्या वह आयोग की राजनीतिक ढाल बनेगी, या ऐसी पारदर्शिता की मांग करेगी जिससे आयोग को किसी राजनीतिक ढाल की जरूरत ही न पड़े? विपक्ष से भी सवाल है—अगर आरोप गंभीर हैं तो क्या उनके साथ पर्याप्त दस्तावेज और प्रमाण सामने रखे जाएंगे? और मीडिया से भी सवाल है—क्या वह दोनों पक्षों के दावों के बीच जाकर सच की पड़ताल करेगा? चुनाव आयोग के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती किसी राजनीतिक दल को संतुष्ट करना नहीं है। उसे उस नागरिक को आश्चस्त करना है जो अपना वोट डालते समय किसी पार्टी पर नहीं, व्यवस्था पर भरोसा करता है। सरकारें बदलती हैं। सत्ता के समीकरण बदलते हैं। राजनीतिक आरोप भी बदलते रहते हैं। लेकिन चुनाव की निष्पक्षता पर जनता का भरोसा कमजोर पड़ जाए, तो उसकी कीमत तबे समय तक चुकानी पड़ सकती है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है—शोर कम हो और रिकॉर्ड सामने आए। आरोपों से ज्यादा उनके जवाब सुनाई दें।

लेखिका– निमिषा सिंह (यह लेखिका के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

(लेखिका– निर्मल रानी)

संक्षिप्तवार्ता

मुख्यमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय में किया स्वच्छता अभियान का शुभारंभ

नई दिल्ली, ०1 अक्टूबर (वेब वार्ता)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के स्वयंसेवकों और अधिकारियों के साथ सफाई अभियान में भाग लिया। अभियान के तहत डीयू परिसर से लेकर कमला नेहरू रिज (बीटा) तक साफ-सफाई की गई और प्रतिभागियों ने स्वच्छता की शपथ ली।

दुबई से 63.26 लाख रुपये का सोना लाए दो यात्री गिरफ्तार

नई दिल्ली, ०1 अक्टूबर (वेब वार्ता)। आईजीआई एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क विभाग ने दुबई से तस्करी कर लाया गया 476 ग्राम सोना बरामद किया है। मामले में दो भारतीय यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों 28 सितंबर को दुबई से फ्लाइट संख्या एफजेड441 से टर्मिनल-3 पहुंचे थे।सीमा शुल्क अधिकारियों ने सामान और यात्रियों की तलाशी ली तो दो सोने की चेन और दो कड़े मिले। बरामद सोने की कीमत करीब 63.26 लाख रुपये बताई गई है। विभाग के अनुसार, यात्रियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे सीमा शुल्क से बचने के लिए सोना दुबई से दिल्ली लाए थे। सोना सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11० के तहत जब्त कर दोनों को धारा 1०4 के तहत गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच जारी है।

राहगिरी दिवस पर रविवार को कार-मुक्त होगा कनाॉट प्लेस

नई दिल्ली, ०1 अक्टूबर (वेब वार्ता)। कनॉट प्लेस को इनर सर्किल चार अक्टूबर को राहगिरी दिवस के तहत कार-मुक्त रहेगा। यहां संगीत, साइकिलिंग, फिटनेस गतिविधियों, स्ट्रीट आर्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। सेंट्रल पार्क में रॉक बैंड यूकोरिया की लाइव प्रस्तुति भी होगी। कार्यक्रम राहगिरी फाउंडेशन, दिल्ली ट्रेफिक पुलिस और फिट इंडिया की ओर से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। फिट इंडिया की हासंडेज ऑन साइकिलज़ पहल के तहत सामुदायिक साइकिलिंग भी होगी। नागरिकों के लिए खेल, इंटरैक्टिव कार्यशालाएं और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। यह कार्यक्रम पांच से सात अक्टूबर तक होने वाले ह्रदयन अड्डा-26६ सम्मेलन का कर्टन-रेजर भी होगा।

मनचले के डर से पढ़ाई छूट जाना चिंताजनक : कोर्ट

नई दिल्ली, ०1 अक्टूबर (वेब वार्ता)। किसी मनचले के डर से छात्रा की पढ़ाई छूट जाना बेहद चिंताजनक है। अदालत ने वजीराबाद इलाके में वर्ष 2०24 में नाबालिग छात्रा का लगातार पीछा करने, अश्लील टिप्पणियां करने और अपराधिक धमकियां देने के मामले में सख्त रुख अपनाने हुए यह टिप्पणी की। तीस हजारों रिश्तत पॉक्सो अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राणा दीपक सिंह ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

कोर्ट ने उसकी करीब दो साल की जेल अवधि को ही उसकी मुख्य सजा स्वीकार करते हुए उस पर 15 हजार रुपये का जुमाना लगाया, जिसे कोर्ट में जमा कराने के बाद उसकी रिहाई के आदेश दिए गए। सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसकी मां ने बताया कि आरोपी की लगातार प्रताड़ना और खीफ के कारण 11वीं कक्षा की छात्रा को अपना नियमित स्कूल छोड़ना पड़ा। वह अब प्लावार् (कॉरपोर्डस) के माध्यम से अपनी पढ़ाई करने को मजबूर है। छात्रा जब भी स्कूल से घर लौटती थी, आरोपी स्कूटी से उसका पीछा कर परेशान करता था।

डीयू में 7 अक्टूबर को कैंपस प्लेसमेंट

नई दिल्ली, ०1 अक्टूबर (वेब वार्ता)। दिल्ली विश्वविद्यालय का केंद्रीय प्लेसमेंट सेल, छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय के तहत 7 अक्टूबर को अवसर 2026 का दूसरा संस्करण आयोजित करेगा। रोजगार मंत्रों के रूप में शुभ की गई इस पहल का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों और संस्थानों से सीधे संवाद का अवसर देने के साथ रोजगार और इंटरनशिप के अवसर उपलब्ध कराना है। यह आयोजन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक नॉर्थ कैंपस स्थित मल्टीपर्पज हॉल, गेट नंबर-2, जीसी नारंग मार्ग में होगा। विश्वविद्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ह्राइअवसर 2०26६ में 85 से अधिक संगठन शामिल होंगे और चार हजार से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है। इसमें सबसे अधिक वार्षिक पैकेज 1० लाख रुपये से अधिक और इंटरनशिप के लिए अधिकतम 60 हजार रुपये प्रतिमाह तक का स्टाइपेंड उपलब्ध कराया जाएगा।

सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, सीआर पाटिल और जी.

किशन रेड्डी ने दिल्ली में चलाया स्वच्छता अभियान

नई दिल्ली, ०1 अक्टूबर (वेब वार्ता)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, सीआर पाटिल, जी. किशन रेड्डी और कई अन्य नेताओं ने गुरुवार को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत अलग-अलग सफाई अभियानों में हिस्सा लिया।

उन्होंने देशभर में इस आंदोलन को और मजबूत करने के लिए नए सिरे को कोशिशें करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुरुवार को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत एक दिन, एक घंटा, एक साथ कार्यक्रम में शामिल हुईं। उन्होंने कमला नेहरू रिज पर मरम्मत कार्यों और सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज एक दिन, एक घंटा, एक साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान में कमला नेहरू रिज पर श्रमदान किया। जब दिल्ली एक साथ



सदस्यों ने उत्साहपूर्वक किया श्रमदान

एनडीएमसी के तहत आने वाले नवयुग स्कूल के अपने दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह छात्रों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता देखकर प्रभावित हुए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज यमुना नदी के तट पर कालिंदी कुंज में आयोजित स्वच्छता अभियान में सहभागिता की। इस अवसर पर टीम- जल शक्ति ने एकजुट होकर स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमनन्ना जी, सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अशोक के. मीणा जी, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग अर्चना वर्मा सहित मंत्रालय व इसके विभिन्न संगठनों के अधिकारी-कर्मचारी, गंगा टास्क फोर्स, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और स्थानीय समुदाय के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक श्रमदान किया।

आगे बढ़ती है, तो बदलाव भी बड़ा होता है। आज हजारों स्वच्छग्रहियों और सदस्यों ने अपने श्रम और सेवा से स्वच्छ

दिल्ली के संकल्प को नई शक्ति दी है। इस अभियान से जुड़े प्रत्येक साथी का हृदय से आभार। आइए, इसी साथ और

पिंक कार्ड के नए नियम से महिलाओं की बढ़ी परेशानी

नई दिल्ली, ०1 अक्टूबर (वेब वार्ता)। दिल्ली की बसों में महिलाओं के निःशुल्क सफर के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड को अनिवार्य किए जाने के पहले दिन नई व्यवस्था से कई महिला यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गुरुवार सुबह पिंक सहेली कार्ड साथ नहीं होने पर कई महिलाओं को बस में यात्रा के लिए किराया देना पड़ा। हालांकि, यात्रियों की परेशानी को जानकारी परिवहन विभाग और दिल्ली परिवहन निगम तक पहुंचने के बाद दोपहर में परिचालकों को पहले दिन पिंक टिकट जारी रखने के निर्देश दिए गए। अब शुक्रवार से पिंक टिकट की व्यवस्था पूरी तरह बंद किए जाने की तैयारी है।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद दिल्ली के अलग-अलग बस अड्डों और प्रमुख मार्गों पर महिला यात्रियों को पिंक सहेली कार्ड दिखाने के बाद ही निःशुल्क टिकट दिया गया। जिन महिलाओं के पास कार्ड नहीं था, उन्हें सामान्य यात्रियों की तरह किराया देकर टिकट लेना पड़ा। सीलमपुर बस अड्डे पर सुबह करीब 8 बजे मौजपुर से बस में सवार हुई पूनम को चाणक्यपुरी जाना था। उन्होंने पिंक सहेली कार्ड बनवा रखा है, लेकिन कार्ड घर पर ही रह जाने के कारण उन्हें बस में निःशुल्क यात्रा

नर्सरी एडमिशन में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाने पर एफआईआर दर्ज

नई दिल्ली, ०1 अक्टूबर (वेब वार्ता)

राजधानी दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लिए फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र जमा करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। यह मामला 2०26-27 शैक्षणिक सत्र के लिए स्पेशल नीड्स वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) कैटेगरी के तहत एडमिशन से जुड़ा है।

एफआईआर के अनुसार, 17 सितंबर को दिल्ली के एक पुलिस थाने में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों को लेकर शिकायत मिली थी। शिकायत में एडमिशन के दस्तावेजों के साथ जमा किए गए दिव्यांग प्रमाण पत्रों और सिफारिशों पत्रों की सत्यता की जांच करने की मांग की गई थी। प्रारंभिक जांच के दौरान दस्तावेजों के साथ लगाए गए दिव्यांग प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया और वे फर्जी पाए गए। एफआईआर में बताया गया है कि इन प्रमाण पत्रों में 41 प्रतिशत सुनने की अक्षमता दिखाई गई थी और ये कथित तौर पर एक सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किए गए थे।

इन्हें किसने बनवाया...

शुरूआती सत्यापन के बाद पुलिस ने 24 सितंबर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(2), 337, 340(2) और 61(2) के तहत एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में जिक्र किया गया है कि कथित घटना की सही तरीख और समय का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने फर्जी प्रमाण पत्रों को तैयार करने और जमा करने के पीछे की परिस्थितियों को खर्षाप्त करने और इसमें शामिल लोगों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। बता दें कि दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी एडमिशन में सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के तहत विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। आरोप है कि कुछ अभिभावकों ने इस कोटे का लाभ लेने के लिए फर्जी नोटों से 41 प्रतिशत हिर्यरिंग इमेयरमेंट (सुनने की क्षमता में कमी) के सर्टिफिकेट बनवाए। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि ये फर्जी सर्टिफिकेट कहां बने, इन्हें किसने बनवाया और क्या इसमें कोई संगठित गिरोह शामिल है।

अंतर-राज्यीय क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी गिरोह का किया भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली, ०1 अक्टूबर (वेब वार्ता)। दिल्ली के साउथ डिस्ट्रिक्ट के साइबर पुलिस स्टेशन ने टेलीग्राम-आधारित टास्क और क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट धोखाधड़ी में शामिल एक अंतरराज्यीय साइबर-फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किए। हालांकि, आरोपियों ने न तो वादा किया गया रिटर्न दिया और न ही निवेश की गई रकम लौटाई, और बाद में शिकायतकर्ता को जवाब देना बंद कर दिया।

शिकायत के बाद साइबर साउथ पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 (4), 319

संपर्क में आया, जहां उसे अच्छे रिटर्न का वादा करके ऑनलाइन टास्क और क्रिप्टोकरेंसी में कैसे निवेश करने के लिए उकसाया गया।

पुलिस ने बताया कि उनकी बातों पर भरोसा करते हुए, शिकायतकर्ता ने आरोपियों के निदेशानुसार 4,66,3०0 रुपए और 3,2०,०00 रुपए की दो किश्तों में कुल 7,86,300 रुपए ट्रांसफर किया। हालांकि, आरोपियों ने न तो वादा किया गया रिटर्न दिया और न ही निवेश की गई रकम लौटाई, और बाद में शिकायतकर्ता को जवाब देना बंद कर दिया।

शिकायत के बाद साइबर साउथ पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 (4), 319



की सुविधा नहीं मिल सकी। उन्हें सीलमपुर तक का किराया देकर टिकट लेना पड़ा। इसके बाद उन्होंने आगे की यात्रा बस के बजाय मेट्रो से पूरी करने का निर्णय लिया।

नए नियम की जानकारी नहीं होने से भी परेशानी

साउथ एक्स बस अड्डे पर दोपहर करीब 2 बजे दिव्या खजूरिया को भी नए नियम के कारण परेशानी हुई। उन्हें होजखास जाना था। दिव्या ने बताया कि अब तक उन्हें महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा का लाभ लेने के



इसी संकल्प के साथ अपनी दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाएं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने नई

लक्ष्मी नगर में भी महिलाओं को देना पड़ा किराया

लक्ष्मी नगर बस अड्डे पर दोपहर करीब 3:15 बजे कई महिला यात्री पिंक सहेली कार्ड के साथ बस में सवार हुईं। परिचालक ने कार्ड देखकर उन्हें निःशुल्क टिकट जारी किया। वहीं, दो महिला यात्रियों के पास कार्ड नहीं था। परिचालक ने उनसे कार्ड के बारे में पूछा और कार्ड नहीं होने की पुष्टि के बाद उन्हें किराया देकर टिकट लेना पड़ा। परिचालक ने महिला यात्रियों को बताया कि निःशुल्क बस यात्रा का लाभ लेने के लिए पिंक सहेली कार्ड बनवाना आवश्यक है।

छतरपुर में वन भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप, सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली, ०1 अक्टूबर (वेब वार्ता)।

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच छतरपुर इलाके में वन विभाग की जमीन पर कथित अतिक्रमण और पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि छतरपुर की 1०0 फुटा रोड और 60 फुटा रोड की गली नंबर-1 में सैकड़ों करोड़ रुपए की वन भूमि पर कब्जे की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने दावा किया कि जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से रातों-रात टीन की दीवारें खड़ी की गई हैं और इनके पीछे पेड़ों की कथित अवैध कटाई के साथ

लाल किला ब्लास्ट केस : 11 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 21 नवंबर तक बढ़ी

नई दिल्ली, ०1 अक्टूबर (वेब वार्ता)। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल एनआईफ कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट ने गुरुवार को मामले के सभी 11 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 21 नवंबर तक बढ़ा दी है।

सभी 11 आरोपियों को गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने उनकी हिरासत बढ़ाने का फैसला सुनाया। राऊज एवेन्यू कोर्ट की एनआईफ कोर्ट अब इस मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम



निर्माण कार्य भी चल रहा है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि तेज डीजे की आवाज की आड़ में हरे और नीले रंग

की टीन की दीवारों के पीछे पेड़ों को काटा जा रहा है। उनके मुताबिक, वन भूमि पर अवैध कब्जे के लिए तेजी से निर्माण

आया नगर में जिम ट्रेनर हत्याकांड के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, ०1 अक्टूबर (वेब वार्ता)। दक्षिण दिल्ली के आया नगर में जिम ट्रेनर की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस हत्याकांड में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान दीपक के रूप में हुई है। आरोपी पर हत्या को अंजाम देने वाले दो शूटर्स को पनाह देने का आरोप है।

दरअसल, दिल्ली के आया नगर इलाके में 14 सितंबर को सुबह 1० बजे जिम ट्रेनर विजय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि दो हमलावरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। विजय जैसे ही जिम से

गतिविधियां की जा रही हैं।

आप नेता ने आरोप लगाया कि छतरपुर के 1०0 फुटा रोड और 60 फुटा रोड इलाके में राजनीतिक संरक्षण में कथित तौर पर बिल्बर माफिया सक्रिय है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कुछ लग्जरी मॉल बनने के बाद वन क्षेत्र की जमीन पर कब्जे को लेकर कथित गतिविधियां बढ़ी हैं। भारद्वाज ने कहा कि यदि वन भूमि पर पेड़ों की कटाई और निर्माण की शिकायतें सही हैं तो यह दिल्ली के पर्यावरण और भविष्य के लिए गंभीर विषय है।

उन्होंने सरकार के पर्यावरण संरक्षण संबंधी दावों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक ओर

आया नगर में जिम ट्रेनर हत्याकांड के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बाहर निकला, पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावरों ने करीब 1० से 12 राउंड गोलियां चलाई थी, जिससे जिम ट्रेनर की मोके पर ही मौत हो गई थी। फायरिंग की आवाज सुनकर इलाके में दहशत फैल गई। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेर लिया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया था।

शुरूआती जांच में पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला मान रही है। हालांकि हत्या के पीछे के असली कारणों का अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। जिसय की किसी से पुरानी दुश्मनी थी या नहीं, इस पहलु पर भी जांच की जा रही है। कुछ महीने पहले भी आया नगर गांव में इसी तरह ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना हुई थी। इससे पहले दिल्ली के नरेला इलाके में भी एक प्रॉपर्टी डीलर की जिम के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें रंगदारी का एंगल सामने आया था।

डिजिटलव फाइनेशियल सबूत बरामद किये

पुलिस ने बताया कि आरोपी पीड़ितों को कैसे ट्रांसफर करने के लिए लुभाने के मकसद से टेलीग्राम-आधारित टास्क और क्रिप्टोकरेंसी निवेश योजनाएं चलाते थे। आरोप है कि बिचिलियों के जरिए कमीशन पर ह्याम्यूल बैंक अकाउंट६ का इंतजाम किया गया और इनका इस्तेमाल धोखाधड़ी से हासिल पैसे को लेने, आगे भेजने और निकालने के लिए किया गया। आरोप है कि पैसे का इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन के लिए भी किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से दो मोबाइल, एक बैंक पासबुक और जरूरी डिजिटल व फाइनेंशियल सबूत बरामद किए।

खाते में 4.66 लाख रुपए का पता चला, जबकि दूसरे खाते में 5.22 लाख रुपए जमा हुए थे।

जांच के आधार पर, आरोपियों करण बिस्वास और मोहित सरकार उर्फ मोनू का पता लगाया गया और उन्हें ऊधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया गया। आगे

की जांच में विनय मंडल की औपचारिक गिरफ्तारी हुई, जो पहले से ही हरियाणा के रोहतक में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अन्य साइबर धोखाधड़ी मामले में हिरासत में था। बाद में उसे तीन दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया।

संक्षिप्तवार्ता

डॉ. गोपाल कृष्ण मिश्र ने नीट-पीजी में 3195वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल कर हरदोई का मान बढ़ाया

हरदोई, वेबवार्ता

अखिल भारतीय स्तर की नीट-पीजी परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता हासिल कर मेडिकल कॉलेज हरदोई में कार्यरत डॉ. गोपाल कृष्ण मिश्र उर्फ शुभम ने अपने परिवार के साथ-साथ पूरे जनपद हरदोई का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। परीक्षा में ऑल इंडिया 3195वीं रैंक प्राप्त करने की जानकारी मिलते ही परिजनों, अधिवक्ताओं और शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई। डॉ. गोपाल कृष्ण मिश्र, डॉ. चमन लाल के पुत्र, सेवानिवृत्त पुलिस आरआई गिरीश चंद्र मिश्र के प्रपौत्र तथा अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव मिश्र के भतीजे हैं। सफलता की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में शुभचिंतक उनके नटवीरन पुलिया स्थित आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने डॉ. शुभम को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी तथा सामूहिक रूप से महाकाल से उनके उज्ज्वल और सफल चिकित्सीय भविष्य की प्रार्थना की।

डीएम का विकास भवन में औचक निरीक्षण, पांच कर्मचारी मिले अनुपस्थित

वेब वार्ता, बहराइच

जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने आज सुबह विकास भवन पहुंचकर विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने जिला विकास अधिकारी, अर्थ एवं संख्या अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तीकरण तथा परियोजना निदेशक डीआरडीए कार्यालय सहित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी तथा जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी तथा पांच कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए अनुपस्थित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने तथा मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी अधिकारी-कर्मचारी समय से कार्यालय में उपस्थित रहकर अपने पदिय दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन सुनिश्चित करें। अर्थ एवं संख्या अधिकारी कार्यालय के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने प्रचालितियों के रख-रखाव को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त कर परियोजनवार नोडल अधिकारी नामित कर नियमित समीक्षा कराए जाने तथा लंबित कार्यों को निश्चित समयसीमा में पूरा कराने के कड़े निर्देश दिए।

राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर मेडिकल कॉलेज में रक्तदाताओं का सम्मान

ब्लड बैंक देवीपाटन मंडल में प्रथम, प्रदेश के टॉप-10 में शामिल

बहराइच। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर महाराजा सुहेलदेव स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय एवं महर्षि बालार्क चिकित्सालय, बहराइच में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा रक्तदाताओं और रक्तदान के क्षेत्र में सहयोग करने वाली संस्थाओं को सम्मानित करना रहा। मेडिकल कॉलेज बहराइच का ब्लड बैंक रक्त उपलब्धता एवं स्वैच्छिक रक्तदान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर रहा है। ब्लड बैंक देवीपाटन मंडल में प्रथम स्थान पर तथा उत्तर प्रदेश के टॉप-10 ब्लड बैंकों में शामिल है। यह उपलब्धि संस्थान के चिकित्सकों, ब्लड बैंक टीम, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा नियमित रक्तदाताओं के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

कार्यक्रम में सर्वप्रथम उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य डॉ. प्रो. संजय खत्री, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधीक्षक का पुष्पाभूष भेंट कर स्वागत किया गया। इसके साथ ही राहा है। ब्लड बैंक देवीपाटन मंडल में प्रथम स्थान पर तथा उत्तर प्रदेश के टॉप-10 ब्लड बैंकों में शामिल है। यह उपलब्धि संस्थान के चिकित्सकों, ब्लड बैंक टीम, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा नियमित रक्तदाताओं के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। कार्यक्रम में सर्वप्रथम उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य डॉ. प्रो. संजय खत्री, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधीक्षक का पुष्पाभूष भेंट कर स्वागत किया गया। इसके साथ ही

अत्याधुनिक प्रोसेसिंग मशीनरी के लिए 2.62 करोड़ से अधिक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

वेब वार्ता, कमर खान

बलरामपुर। आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर को स्वच्छ,सुंदर और कूड़ा-मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नगर क्षेत्र में वर्षों से एकत्रित लगभग 65,000 मीट्रिक टन लिगेसी वेस्ट के वैज्ञानिक एवं पूर्ण निस्तारण के लिए अत्याधुनिक प्रोसेसिंग मशीनरी की स्थापना को 2 करोड़ 62 लाख 94 हजार की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

नगर पालिका अध्यक्ष डॉ.धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप यह स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तथा नगर विकास मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग को महत्वपूर्ण बताया गया है।

वैज्ञानिक तरीके से होगा कचरे का निस्तारण

प्रस्तावित अत्याधुनिक प्रोसेसिंग



मशीनरी के माध्यम से नगर में वर्षों से जमा लिगेसी वेस्ट के विशाल ढेरों की वैज्ञानिक पद्धति से छंटाई,प्रसंस्करण और समुचित निस्तारण किया जाएगा। इससे पुराने कचरे के ढेर की व्यवस्थित रूप से समाप्त करने में मदद मिलेगी तथा नगर के पर्यावरण और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस प्रगति होगी। लिगेसी वेस्ट के

वैज्ञानिक निस्तारण से कूड़ा निस्तारण स्थल पर लंबे समय से जमा कचरे का बोझ कम होगा और नगर में स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। आधुनिक तकनीक के माध्यम से कचरे के विभिन्न घटकों को अलग-अलग करने तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निस्तारण किए जाने की व्यवस्था की

जावेद हबीब ने लखनऊ में फ्रेंचाइजी मीट का आयोजन किया

वेब वार्ता, लखनऊ। देश की प्रमुख हेयर एवं ब्यूटी सैलून चेन जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी लिमिटेड द्वारा गुर लखनऊ में फ्रेंचाइजी मीट 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जैस्पर हॉल, सेलेस्टियल मैनर, ओमैक्स हजरतगंज, सेक्टर-7, अमर शहीद पथ, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में किया गया।

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े जावेद हबीब के फ्रेंचाइजी पार्टनर्स एवं सैलून संचालकों ने भाग लिया। फ्रेंचाइजी मीट का उद्देश्य पार्टनर्स के साथ सवाद को मजबूत करना, व्यवसाय के नए अवसरों पर चर्चा करना तथा ब्रांड की भविष्य की विकास रणनीतियों को साझा करना रहा।



इस अवसर पर प्रसिद्ध हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के साथ हेयर एवं ब्यूटी इंडस्ट्री में बदलते ट्रेंड्स, ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं, व्यवसाय विस्तार और भविष्य की संभावनाओं पर

चर्चा की। उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइजी नेटवर्क की सफलता में पार्टनर्स की भूमिका महत्वपूर्ण है और निरंतर ज्ञान, बेहतर सेवाओं तथा मजबूत ग्राहक अनुभव के माध्यम से व्यवसाय को आगे



बढ़ाया जा सकता है।

कार्यक्रम में मास्टर फ्रेंचाइजी - प्रशांत सिंह ने भी उत्तर प्रदेश में ब्रांड के विस्तार और फ्रेंचाइजी नेटवर्क की संभावनाओं को लेकर अपने विचार साझा

वृद्धजन दिवस पर सम्मान भी, संवेदना भी और सेवा भी

वृद्धजनों के बीच मनाया वृद्धजन दिवस



वेब वार्ता, आलोक चतुर्वेदी

ललितपुर। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर गुरुवार को ललितपुर वृद्धावस्था आश्रम में सम्मान, संवेदना और सेवा का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिविल जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवप्रिय सारस्वत रहे। इस अवसर पर ललितपुर पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (एलपीजीसीएल) की ओर से सीएसआर के तहत करीब दो लाख रुपये की लागत के 10 एयर कूलर वृद्धावस्था आश्रम को भेंट किए गए। यह सहयोग जिलाधिकारी सत्यप्रकाश के मार्गदर्शन में प्रदान किया गया। एलपीजीसीएल के वाइस प्रेसिडेंट राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि वृद्धजन समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनके जीवन का अनुभव और संस्कार आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक हैं। उन्होंने समाज से बुजुर्गों की सेवा, सम्मान और उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहने की अपील की। मुख्य अतिथि देवप्रिय सारस्वत ने कहा कि बुजुर्गों का अनुभव जीवन की कठिन परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शन करता है। उनकी सेवा केवल दायित्व नहीं, बल्कि ऐसा पुण्य कार्य है, जिससे आत्मिक संतोष मिलता है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सोनाली जैन ने आश्रम से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वृद्धजनों की सेवा और सम्मान समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में एलपीजीसीएल के सीएसआर हेड राजेन्द्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार राजीव शुक्ला, प्रमोद पटैरिया एवं उमाकांत सुड़ले सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

साझाकरण, व्यवसाय विकास, ग्राहक अनुभव और भविष्य की रणनीति से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम ने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को एक साझा मंच प्रदान किया, जहां उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और ब्रांड के साथ भविष्य की विकास योजनाओं पर विचार-विमर्श किया।

सहयोग देने कर रह है कार्य

जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी लिमिटेड देशभर में अपने सैलून एवं हेयर एजुकेशन नेटवर्क के विस्तार के साथ फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के लिए नए व्यवसायिक अवसर विकसित करने और उन्हें निरंतर सहयोग प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है।

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर अल्लीपुर वृद्धाश्रम पहुंचे डीएम, बुजुर्गों को बांटे उपहार



वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

जानकारी भी ली।

वृद्धजनों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मौके पर चिकित्सा शिविर भी लगाया गया। शिविर में वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यकतानुसार दवाओं का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

कार्टवाई की जायेगी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलााधिकारी राहुल पाण्डेय ने कहा कि वरिष्ठजनों के बीच आकर उन्हें आत्मीयता और सम्मान देने का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। उन्होंने सभी वृद्धजनों को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की शुभकामनाएं देते हुए भरोसा दिलाया कि उनकी ओर से दिए जाने वाले सुझावों और समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

तीन सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर गरजे शिव सैनिक

वेब वार्ता, मुरादाबाद। शिवसेना पश्चिमी उत्तर प्रदेश एकनाथ शिंदे गुट की मुरादाबाद जिला इकाई ने तीन सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया।

पदाधिकारी संगठन के जिला प्रमुख नन्हें चौधरी उर्फ दिनेश चौधरी के नेतृत्व में अंबेडकर पार्क से पार्टी के झंडे और बैनरों के साथ जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को पेश किया गया जिसमें कहा गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश देश का अत्यंत महत्वपूर्ण कृषि औद्योगिक व्यापारिक एवं आर्थिक क्षेत्र है यह क्षेत्र कृषि भूजल एवं वीनी उद्योग दुग्ध उत्पादन लघु एवं मध्यम उद्योग व्यापार तथा सेवा



क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है इतने बड़े और महत्वपूर्ण क्षेत्र की प्रशासनिक

आवश्यकताओं न्याय तक सरल पहुंच तथा संतुलित विकास को देखते हुए

पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक पृथक राज्य पश्चिम प्रदेश के रूप में गठित किए जाने

की मांग लंबे समय से उठती रही है ज्ञापन के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्स ब्रांच स्थापित करने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जाए। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के दौरान शिवसेना जिला प्रमुख नन्हें चौधरी उर्फ दिनेश चौधरी के अलावा मंडल प्रमुख गूडू सेनी प्रेश सचिव राम प्रसाद प्रजापति महानगर प्रमुख मनोज कुमार सहित भारी संख्या में शिव सैनिक मौजूद रहे। इस अवसर पर पुलिस की जानिब से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे जुलूस के साथ भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी।

महिला सम्मान पर कथित टिप्पणी से उबला हरदोई, शराफत अली के खिलाफ सड़कों पर उतरीं महिलाएं

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष शराफत अली की कथित विवादित टिप्पणी से हरदोई की सियासत में उबाल है। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती पीके वर्मा के खिलाफ बयान के विरोध में गुरुवार को भाजपा महिला मोर्चा समेत कई संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और शराफत अली का पुत्ला फूँका। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।मामला बुधवार को गोपात्मऊ में आयोजित सपा के डब्बू सम्मेलन का है। आरोप है कि

आरक्षण पर बोलते हुए शराफत अली ने जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जातिसूचक और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। इसका वीडियो वायरल होते ही विवाद गहरा गया।

आरक्षण संवैधानिक अधिकार, निजी कृपा नहीं

कथित बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए प्रेमावती वर्मा ने कहा कि वैचारिक असहमति अलग बात है, लेकिन किसी महिला को सामाजिक पृष्ठभूमि को निशाना बनाकर नीचा दिखाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, रमैनै शिक्षिका के रूप में कार्य करने के बाद राजनीति में कदम रखा है। आरक्षण संविधान



की देन है, किसी नेता की व्यक्तिगत

कृपा नहीं। उन्होंने मामले की पुलिस

शराफत अली शराफत अली का महिला नेताओं से जुड़ा यह पहला विवाद नहीं है। इससे पहले सपा की ही पूर्व सांसद ऊषा वर्मा और पूर्व विधायक राजेश्वरी देवी से संबंधित कथित सामग्री को लेकर वे अपनी ही पार्टी में घिर चुके हैं। हालांकि, तब उन्होंने वीडियो को एडिटेड बताया था। इसी खींचतान के बीच सपा नेतृत्व ने पूर्व में हरदोई की पूरी जिला कार्यकारिणी भंग कर दी थी।

राजनीतिक बहस या भाषा का गिरता स्तर? प्रदर्शनकारी संगठनों का कहना है कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय

महिलाओं के प्रति ऐसी भाषा राजनीतिक मयदां के खिलाफ है। फिलहाल, हरदोई में यह मुद्दा महज चुनावी या नीतिगत बहस न रहकर

महिला सम्मान और राजनीतिक शुचिता की लड़ाई में बदल चुका है। अब सबकी नजरें पुलिसिया जांच और कानूनी कार्रवाई पर टिकी हैं।

फैमिली आईडी की धीमी रफ्तार पर सीडीओ सख्त, अधिकारियों को अंतिम चेतावनी

वेब वार्ता, ललितपुर,आलोक चतुर्वेदी। फैमिली आईडी-एक परिवार एक पहचान योजना की धीमी प्रगति पर मुख्य विकास अधिकारी रीनाश चोहान ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्धारित समय में फैमिली आईडी बनाने का कार्य पूरा नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक एवं विभागीय कार्रवाई की जाएगी। विकास भवन में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में योजनावार लाभार्थियों की फैमिली आईडी बनने की स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा में सामने आया कि कुल 1,50,084 लाभार्थियों के सापेक्ष 81,841 की फैमिली आईडी बनना अभी शेष है।

फॉर्म-6 में बदलाव पर राहुल गांधी के सवाल, पूछा- आदेश किसने दिया ?

राहुल ने टीसीएस से जुड़े सवाल भी उठाए; चुनाव आयोग ने एसआईआर पूरी कर चुके राज्यों में फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा हटाई

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑनलाइन फॉर्म-6 में किए गए बदलाव को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं।

सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी ने दावा किया कि फॉर्म-6 में बदलाव गैरकानूनी तरीके से किया गया और कहा कि चुनाव आयोग के अपने आयुक्तों ने भी इस पर आपत्ति

दर्ज की है।

राहुल गांधी ने इस बदलाव को लेकर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि चुनाव आयोग में किस अधिकारी ने टीसीएस को बदलाव करने का निर्देश दिया और कंपनी की ओर से इस पर किसने मंजूरी दी। साथ ही उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या बदलाव लागू करने के लिए टीसीएस पर किसी तरह का दबाव था। ये राहुल गांधी के आरोप और सवाल हैं; उपलब्ध रिपोर्टों में इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। एसआईआर को लेकर पहले से



विवाद

फॉर्म-6 में बदलाव का मुद्दा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चल रही

राजनैतिक बहस के बीच सामने आया है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध कार्यक्रमों

की घोषणा की है। कांग्रेस सहित विपक्षी दल चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मामलों पर चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे हैं।

चुनाव आयोग ने क्या बदलाव किया ?

चुनाव आयोग ने उन राज्यों में, जहां एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ऑनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त एसआईआर घोषणा को वापस लेने का फैसला किया है। इस घोषणा के तहत पहले नए मतदाता के पंजीकरण से संबंधित अतिरिक्त जानकारी मांगी जा रही थी। आयोग के इस फैसले पर दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों का भी उल्लेख रिपोर्टों

में किया गया है।

आयोग के आदेश के मुताबिक जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां नए मतदाता के पंजीकरण के लिए सामान्य फॉर्म-6 का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया होनी है, वहां संबंधित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान लागू रहेंगे।

फॉर्म-6 का इस्तेमाल नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए किया जाता है और चुनाव आयोग के वोटर सेवा पोर्टल पर इसके जरिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

बॉम्बे हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा सकता नाम

कोर्ट ने कहा- सॉफ्टवेयर की तकनीकी दिक्कत कानून से ऊपर नहीं, बिना सुनवाई मतदाता का नाम हटाने पर उठाए सवाल

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची किसी व्यक्ति का नाम हटाने का आधार नहीं बन सकती। साथ ही प्रशासनिक सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या को कानून से ऊपर नहीं रखा जा सकता।

मामला पेश सालगांवकर और उनके परिवार के पांच सदस्यों से जुड़ा है। परिवार ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू होने से पहले वे सांता क्रूज

विधानसभा क्षेत्र में ही दूसरे मकान में चले गए थे। पता बदलने के लिए बृथ लेवल अधिकारी ने उन्हें फॉर्म-8 भरने को कहा। हालांकि जांच के दौरान ईआरओनेट प्रणाली में उनका मतदाता पहचान पत्र रिकॉर्ड नहीं मिला। अधिकारियों को आवेदन स्वीकार करने के बजाय केवल उसे अस्वीकार करने का विकल्प दिखाई दिया।

इसके बाद परिवार को बताया गया कि उनके मतदाता पहचान पत्र को सूची से हटा दिया गया है। ऐसी स्थिति में फॉर्म-8 पर कार्रवाई संभव नहीं थी और उन्हें फॉर्म-6 भरने की



सलाह दी गई। याचिकाकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वे

पहले से मतदाता थे और केवल पता बदल रहे थे, इसलिए उनके लिए

फॉर्म-8 ही उचित था।

कोर्ट ने फॉर्म-6, 7 और 8 का बताया अलग उद्देश्य न्यायमूर्ति अमित एस. जमसांडेकर और न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस की पीठ ने कहा कि फॉर्म-6 नए मतदाता के पंजीकरण, फॉर्म-7 नाम हटाने और फॉर्म-8 पता बदलने या अन्य संशोधन के लिए है। अदालत ने सवाल किया कि यदि कोई व्यक्ति पहले से मतदाता है तो केवल सॉफ्टवेयर की वजह से उसे नया मतदाता कैसे माना जा सकता है। पीठ ने यह भी पूछा कि बिना

संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए मतदाता सूची से नाम हटाने का अधिकार आयोग को किस कानून के तहत मिला है। अदालत ने कहा कि अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी केवल सॉफ्टवेयर पर नहीं डालनी चाहिए।

कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि यदि सॉफ्टवेयर फॉर्म-8 स्वीकार नहीं करता तो अधिकारियों के पास तकनीकी बाधा को दूर कर सही आदेश दर्ज करने की व्यवस्था क्यों नहीं है। पीठ ने आशंका जताई कि ऐसी व्यवस्था से बड़ी संख्या में मतदाता प्रभावित हो सकते हैं।

समंदर से आकर नहर में गिरते ही स्टार बन गई शार्क



सियोल। दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में इन दिनों एक शार्क ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। आमतौर पर शार्क को समुद्र में देखा जाता है, लेकिन यहां एक शार्क पिछले 12 दिनों से शहर की एक कृत्रिम नहर में फंसी हुई है। उसे देखने के लिए अब तक 6 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। स्थानीय लोगों ने घ्यार से इस शार्क का नाम हलबूकांग-ईल्ड रखा है। अब समुद्री अधिकारियों ने उसे सुरक्षित तरीके से नहर से निकालकर खुले समुद्र में पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिया है।

शार्क को देखने और सेल्फी लेने की लगी होड़

यह शार्क पहली बार 18 सितंबर को बुसान के नॉर्थ पोर्ट इलाके के एक वॉटरफ्रंट पार्क की नहर में दिखाई दी थी। अधिकारियों ने शुरू में उसे वहां से बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन शार्क नहर छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुई। कई प्रयासों के बाद अधिकारियों ने अभियान रोक दिया। इस बीच शार्क को देखने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। देखते ही देखते वह बुसान के इस इलाके का एक अनोखा आकर्षण बन गई। समुद्र में शार्क देखना अपने आप में रोमांचक अनुभव है, लेकिन शहर के बीचोबीच बनी एक नहर में शार्क का दिखाई देना लोगों के लिए बेहद असामान्य घटना है। इसी वजह से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी उसे देखने पहुंच रहे हैं। शार्क को दिया गया हलबूकांग-ईल्ड नाम भी लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया है। यह नाम बुसान के नॉर्थ पोर्ट यानी हलबुकहंगम और कोरियाई भाषा के एक सामान्य प्रत्यय को जोड़कर बनाया गया है। मंगलवार को बुसान कोस्ट गार्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ फिशर्रीज साइंस और अन्य संबंधित एजेंसियों ने शार्क को सुरक्षित बाहर निकालने की तैयारी शुरू की। पहले दो नावों की मदद से पानी की धार छोड़कर शार्क को नहर से समुद्र की ओर ले जाने की कोशिश की जाएगी। अगर यह तरीका सफल नहीं हुआ तो नहर की चौड़ाई और गहराई के अनुसार तैयार किए गए विशेष जाल का इस्तेमाल किया जाएगा।

आसमान से 180 लोगों को बचाने वाले स्मित मच्छार की कैसी है हालत

दुबई। दुबई से इजरायल के तेल अवीव जा रही एक विमान में एक अभूतपूर्व घटना के बाद भारतीय सह-पायलट स्मित मच्छार हीरो बनकर उभरे हैं। खुद बुरी तरह घायल होने के बावजूद, उन्होंने सेकड़ों यात्रियों की जान बवाई, जब उनके साथी पायलट ने उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने के इरादे से उन पर हमला कर दिया। फिलहाल, मच्छार सऊदी अरब के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। यह घटना फ्लाईदुबई के बोइंग 737 विमान में लगभग 34,000 फीट की ऊंचाई पर हुई। बताया जा रहा है कि हमलावर पायलट का मकसद विमान को क्रैश कराना था। इस हमले में गुजरत के निवासी स्मित मच्छार गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद, यात्रियों ने एकजुट होकर हमलावर को काबू करने में उनकी मदद की। इजरायल



के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बाद में पुष्टि की कि सह-पायलट ने दूसरे पायलट पर चाकू से हमला कर विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने का प्रयास किया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस

हाथापाई के दौरान, दुबई से उड़ान भरने के लगभग ढाई घंटे बाद, विमान 34 सेकंड के भीतर 33,000 फीट की ऊंचाई से तेजी से गिरकर 17,000 फीट पर आ गया। घटना के समय, विमान ने 7500 का कोड भी

भेजा, जिसे आमतौर पर हाईजैक या आतंकी हमले के संकेतों के रूप में समझा जाता है। इस कोड ने हवाई यातायात नियंत्रण को सतर्क करने और सुरक्षा एजेंसियों को संभावित खतरे के लिए तैयार रहने का संदेश दिया।

रियाद में भारतीय दूतावास ने स्मित मच्छार के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखने की बात कही है। दूतावास और जेद्दा में भारतीय कॉन्सुलेट, फ्लाईदुबई की उस प्लाइट के बहादुर भारतीय पायलट की सेहत पर पैनी नजर रखे हुए हैं, जिन्हें सऊदी अरब के उत्तर पश्चिम में तबुक शहर में भर्ती कराया गया है और सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। दूतावास ने बताया है कि उनकी हालत स्थिर है और उनके परिवार के साथ भी संपर्क स्थापित कर लिया गया है, जिन्हें उनके स्वास्थ्य से संबंधित अपडेट्स नियमित रूप से दिए जा रहे हैं।

अध्यक्ष राजा वडिंग का इस्तीफा, नए चेहरे की तलाश में कांग्रेस

चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक छह महीने पहले कांग्रेस पार्टी में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली है। पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

यह कदम तब उठा जब हाल ही में भूपेश बघेल की जगह सचिन पायलट को पंजाब का प्रभारी नियुक्त किया गया। इस राजनीतिक घटना

के बाद अब नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अटकलें तेज हो चुकी हैं और पार्टी अगले 24 से 48 घंटों में नए नाम की घोषणा कर सकती है।

नए अध्यक्ष पद की दौड़ में कई नाम प्रमुखता से शामिल हैं। पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला इससे पूर्व में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। वह हिंदू बनिया समुदाय से आते हैं और पंजाब सरकार में मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस ने हाल ही में उन्हें चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष भी बनाया था। राज्य के हिंदू मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस उनके चेहरे पर दांव खेल सकती है। अन्य



दावेदारों में जालंधर कैट से विधायक और पूर्व हॉकी कप्तान परगत सिंह (जाट सिख) और गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा (जाट सिख, पूर्व उप मुख्यमंत्री) भी शामिल हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, विजय इंदर सिंगला के अध्यक्ष बनने के बाद

चुनाव अभियान समिति की कमान दलित चेहरे के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी को दिए जाने की संभावना है।

वडिंग का इस्तीफा पार्टी के भीतर लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी और अंदरूनी कलह का परिणाम है। उन्होंने तब पंजाब कांग्रेस की कमान संभाली थी जब आम आदमी पार्टी (आप) से करारी हार के बाद पार्टी आंतरिक खींचतान से जूझ रही थी। हालांकि, उनके कार्यकाल में भी यह स्थिति नहीं सुधरी और हाल के महीनों में यह अपने चरम पर पहुंच गई थी। पंजाब

कांग्रेस में दो प्रमुख गुट आमने-सामने थे - एक राजा वडिंग, जिसे भूपेश बघेल का समर्थन प्राप्त था, और दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का गुट, जिसे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा का समर्थन मिल रहा था। जुलाई में हाईकमान द्वारा वडिंग को पद पर बनाए रखने के फैसले ने गुटबाजी को और गहरा कर दिया था। गुटबाजी की खबरें राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनने के बाद, कांग्रेस हाईकमान ने सितंबर महीने में भूपेश बघेल को पंजाब प्रभारी पद से

हटाकर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट को यह जिम्मेदारी सौंपी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी माने जाने वाले सचिन पायलट का पहला काम सभी गुटों को एक मंच पर लाकर एकजुटता का संदेश देना था। इस पहल का चन्नी, वडिंग और बाजवा सहित सभी नेताओं ने स्वागत किया। सितंबर के अंतिम दिनों में राजा वडिंग का इस्तीफा ले लिया गया, ताकि विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में नए सिरे से संतुलन स्थापित किया जा सके।

पीएम रहमान ने दुर्गा पूजा अनुदान 5 करोड़ किया, 5 दिन की छुट्टी भी दी

ढाका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने इस साल दुर्गा पूजा के लिए सरकारी खजाना खोलते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उन्होंने दुर्गा पूजा के लिए अनुदान की राशि बढ़ाकर 5 करोड़ টাকা कर दी है। इसके साथ ही, सरकारी कर्मचारियों के लिए दुर्गा पूजा की छुट्टी को भी बढ़ाकर पांच दिन कर दिया गया है। सरकार के इस कदम को अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय तक पहुंचाने और उनके बीच विश्वास बहाल करने की एक बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, हिंदू धार्मिक कल्याण ट्रस्ट ने पहले पूजा के लिए 4 करोड़ টাকা का अनुदान मांगा था, लेकिन प्रधानमंत्री के विशेष ध्यान और निर्देश के बाद इस राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ টাকা कर दिया गया। इसी तरह, बौद्ध धार्मिक कल्याण ट्रस्ट ने अपने कथिन चीवर दान उत्सव के लिए 2 करोड़ টাকা की मांग की थी, जिसे बढ़ाकर 3 करोड़ টাকা कर दिया गया है। ये बढ़ोतरी सरकार की तरफ से अल्पसंख्यकों के प्रति दिखाए गए सद्भाव का प्रतीक है।

सरकार ने हिंदू समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए दुर्गा पूजा की सरकारी छुट्टी भी बढ़ा दी है। अब तीन दिन की आधिकारिक छुट्टी के साथ वीकेड (शनिवार-रविवार) को मिलाकर कुल पांच दिन की छुट्टी मिलेगी, जिससे त्योहार मनाने वालों को अधिक समय मिल सकेगा। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे थे। विशेष रूप से 2024 में शेख हसीना सरकार के गिरने और मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार



के दौरान अल्पसंख्यकों, खासकर

हिंदुओं पर हमलों में वृद्धि देखी गई

था। इस स्थिति को देखते हुए, पड़ोसी देश भारत ने भी कई बार बांग्लादेश के अधिकारियों के सामने अल्पसंख्यक सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले संबोधन में उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार सभी नागरिकों के लिए देश को सुरक्षित बनाएगी, चाहे वे किसी भी धर्म, विचार, या जातीयता के हों। हाल ही में वे जन्माष्टमी के कार्यक्रम में भी

शामिल हुए थे, जहां उन्होंने नागरिकों से खुद को बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक न मानकर, स्वयं को केवल बांग्लादेशी के रूप में देखने की अपील की थी। इस साल पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने का ऐलान किया गया है। गुह मंत्री सलाहद्वीन अहमद ने त्योहार के लिए बड़ी हुई सुरक्षा, सरकारी मदद और लंबी छुट्टी की घोषणा की। अधिकारियों को त्योहार की निगरानी के लिए नेशनल टेलीकम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सेंटर के मोबाइल ऐप का उपयोग करने को कहा गया है।

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की एयरस्ट्राइक, 9 लोगों की मौत



नई दिल्ली। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान के सीमावर्ती प्रांतों में हवाई हमले किए हैं, जिनमें कुनार और हेलमंद प्रांत मुख्य रूप से प्रभावित हुए हैं। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कुल 9 अफगानी नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि 11 अन्य लोग घायल हुए हैं। अफगानिस्तान के प्रवक्ता के मुताबिक, पाकिस्तानी विमानों ने जानबूझकर नागरिक घरों को निशाना बनाया, जिसके परिणामस्वरूप तीन घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। इस घटना ने दोनों देशों के बीच तनाव को और गहरा कर दिया है।

गुरुवार तड़के करीब 3 बजे कुनार प्रांत के शेलेटन जिले की चोगाम घाटी में एक नागरिक के घर पर बमबारी का दावा किया गया। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि इस हमले में पांच लोगों की मौत हुई और तीन अन्य घायल हुए। मारे गए लोगों में ज्यादातर बच्चे शामिल थे, जिनकी उम्र बेहद कम बताई जा रही है। हमले के तुरंत बाद, इलाके में व्यापक बचाव अभियान चलाया गया, जहां मलबे से लोगों को बाहर निकालने और गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए नजदीकी अस्पतालों में ले जाने का काम किया गया। इस बर्बर हवाई हमले के बाद स्थानीय आबादी में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा और नाराजगी देखी जा रही है। वहीं, हेलमंद प्रांत के गरमसर जिले के सफर इलाके में भी नागरिक घरों पर हवाई हमला किए जाने की बात सामने आई है। इस हमले में शेष चार नागरिकों की मौत और आठ अन्य के घायल होने की खबर है। अफगानिस्तान तालिबान के प्रवक्ता जिबुल्लाह मुजाहिद ने इस घटनाक्रम पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछली रात पाकिस्तानी विमानों ने कुनार के शेलेटन जिले के चोगाम इलाके और हेलमंद के गरमसर जिले के सफर इलाके में नागरिक घरों पर बमबारी की।

नीला ड्रम कांड: दोषी ठहराए गए मुस्कान और साहिल

मेरठ। बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुख्य आरोपी उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को बुधवार को जिला अदालत ने दोषी करार दे दिया है। दोनों को 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के दौरान मुस्कान की गोंद में उसकी नन्ही बेटी भी मौजूद रही। कार्यवाही पूरी होने और दोषी करार दिए जाने के बाद दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से रोते हुए बाहर निकले।



साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और पत्रावलियों के आधार पर यह अहम फैसला सुनाया। जिला जज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पत्रावलियों पर मौजूद तमाम साक्ष्य पूरी तरह से इस बात को साबित करते हैं कि इन दोनों ने मिलकर ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया।

कोर्ट ने दोनों दोषियों को सजा पर अपना पक्ष रखने और यह बताने के लिए कि उनकी सजा क्यों कम की जानी चाहिए, पूरे 15 दिन का समय दिया है। इस अवधि के भीतर दोषियों को अपनी सफाई या दलील अदालत के समक्ष रखनी होगी, जिसके बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि बुधवार को फैसले का दिन होने के कारण सुबह से ही दोनों दोषी बेचैन दिखे। मुस्कान दिन भर पूजा-पाठ में ही लगी रही और उसने दिन में भी मामूली रूप से ही खाना खाया था। अदालत के दोषी करार दिए जाने के बाद दोनों काफी उदास हो गए और रात में खाने से भी इनकार कर दिया। जेल अधिकारियों के मुताबिक, कार्यवाही के बाद भी दोनों एक-दूसरे से दूरी बनाए रहे। मुस्कान और साहिल ने एक-दूसरे की तरफ देखा तक नहीं और अपने-अपने बैरक की ओर चले गए। सौरभ राजपूत की हत्या के इस मामले में पुलिस ने गहन जांच के बाद मुस्कान और साहिल के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए थे। इस हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी और अब अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। 14 अक्टूबर को सजा का ऐलान होने के साथ ही इस बहुचर्चित मामले का अगला अध्याय पूरा होगा।

आईएसएल लीग क्लब-आधारित मॉडल की ओर बढ़ी, अरुण यादव बने सीईओ

नई दिल्ली। इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) अब इस फुटबॉल लीग को क्लब-आधारित मॉडल में बदल रही है। इसी के तहत ही करण यादव को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। करण को जिम्मेदारी लीग को व्यवसायिक रूप से सशक्त बनाने के साथ ही प्रसारण रणनीति और प्रशंसकों के साथ संबंधों को बेहतर बनाना है। करण ऐसे समय पर कप्तान संभाल रहे हैं जब लीग अपने पुराने मास्टर-राइट्स मॉडल से निकल क्लब-आधारित व्यवसायिक मॉडल की ओर बढ़ रही है। अब तक लीग को फुटबॉल स्पोर्ट्स डिवलवमेंट लिमिटेड के साथ काम करते हुए वित्तीय परेशानियों से जूझना पड़ रहा था।

वहीं मुख्य कार्यकारी बने यादव ने लीग में अपनी भूमिका को लेकर उत्साहित होते हुए कहा कहा, हूआईएसएल एक नये अध्याय में प्रवेश कर रही है और मैं आगे की दिशा तय करने में योगदान देने के इस अवसर को लेकर गर्व का अनुभव कर रहा हूं। क्लब-आधारित मॉडल हमें क्लबों और आईएलएल की मैनेजिंग कमेटी के साथ काम करने के लिए एक मजबूत आधार देता है। हम सभी का लक्ष्य लीग और भारतीय फुटबॉल को आगे ले जाना है।

उन्होंने लीग ऑफिस को मजबूत करने और आईएसएल की व्यावसायिक स्थिति को बेहतर बनाने की प्राथमिकता भी बताई। साथ ही कहा, हमारा ध्यान एक



मजबूत और प्रभावी लीग ऑफिस तैयार करने, लीग की व्यवसायिक और प्रसारण पेशकश को मजबूत करने, प्रशंसकों के साथ जुड़ाव बढ़ाने और ऐसा माहौल बनाने पर होगा, जहां क्लब स्थाई रूप से आगे बढ़ सके। करण यादव ने आगे कहा की हमारा प्रयास एक ऐसी लीग तैयार करना है, जो आर्थिक रूप से अधिक मजबूत, अधिक जुड़ी हुई हो और भारतीय फुटबॉल को आगे ले जा सके।

इससे पहले जुलाई में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) और इंडियन सुपर लीग की मैनेजिंग कमेटी ने क्लब-आधारित व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट की थी। इसमें बताया गया था कि अब आगे आईएसएल के व्यासासिक अधिकार खों के पास होंगे। वहीं एआईएफएफ प्रशासनिक नियंत्रण अपने पास रखेगा। इसका लक्ष्य लीग को अधिक व्यापक क्लब-आधारित व्यवस्था की ओर ले जाना है। करण यादव के के पास लंबा कारोबारी अनुभव है। वह राइट्स होल्डर्स, ब्रांड्स और ग्लोबल एजेंसियों के साथ काम कर चुके हैं। इससे पहले वह जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्सर्स में मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी रहे रहे थे।

टेस्ट क्रिकेट में अश्विन और मुरलीधरन के इस रिकार्ड की बराबरी नहीं कर पाया कोई खिलाड़ी

मुम्बई। भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर आर अश्विन और श्रीलंकाई टीम के महान स्पिनर मृथैया मुरलीधरन के नाम एक अनोखा रिकार्ड है जिसकी बराबरी आज तक कोई अन्य खिलाड़ी नहीं कर पाया है। इन दोनों के ही नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक 11-11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतने का विश्व रिकार्ड है। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो अपने प्रदर्शन से सीरीज का रुख पलट दे। टेस्ट क्रिकेट के लंबे प्रारूप में में यह सम्मान हासिल करना किसी भी खिलाड़ी के करियर की

सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। ये उसकी निरंतरता और मैच-विजेता क्षमता को दिखाती है। मुरलीधरन ने साल 1992 से 2010 के बीच अपने 18 साल लंबे करियर में 133 टेस्ट मैच और कुल 61 सीरीज खेलीं। उन्होंने अपनी जादुई फिरकी से दुनिया भर के बल्लेबाजों को नवाते हुए 11 बार पूरी सीरीज पर अपनी अमिट छाप छोड़ी और यह पुरस्कार जीता। मुरलीधरन की घुमती गेंदों और उनकी मशहूर हाइड्रसल्लू का सामना करना उस दौर में किसी भी विदेशी टीम के लिए सबसे कठिन चुनौती माना जाता था। वहीं दूसरी ओर,

डब्ल्यूपीएल के लिए आरसीबी ने ग्रेस सहित चार खिलाड़ियों को बाहर किया

अरुंधति सहित 13 खिलाड़ियों को रखा बरकरार

मुम्बई। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट (डब्ल्यूपीएल) के लिए नीलामी 28 अक्टूबर को कोच्चि में आयोजित की जाएगी। इसी को देखते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने ग्रेस हैरिस को रिलीज कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैरिस ने 2026 में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके बाद भी उन्हें टीम ने बरकरार नहीं रखा है। ग्रेस हैरिस के अलावा लिंसी स्मिथ, डी. हेमलता और गौतमी

नायक को भी आरसीबी ने बाहर कर दिया है। वहीं टीम ने 13 खिलाड़ियों को बरकरार रखा है। इनमें अरुंधति रेड्डी, प्रलुषा कुमार, ऋचा घोष, स्मृति मंधाना, प्रेमा रावत, सयाली सतघरे, पूजा वस्त्राकर, राधा यादव और श्रेयंका पाटिल शामिल हैं। विदेशी खिलाड़ियों में लैरिन बेल, एलिस पेरी, नादिन डी क्लर्क और जॉर्जिया चोल को टीम ने अपने साथ रखा है। दिग्गज ऑलराउंडर एलिस पेरी



के इस सत्र में खेलने की उम्मीद है। वह पिछले सत्र में शामिल नहीं थी। आरसीबी ने उन्हें टीम में बरकरार रखा था। 2 बार की चैंपियन आरसीबी के पास नीलामी के लिए 1.15 करोड़ रुपये का पर्स बचा है और उसे 5 खिलाड़ियों की जगह भरनी है। इनमें 2 विदेशी खिलाड़ियों के लिए जगह है। ऐसे में वह कई नये खिलाड़ियों को खरीद सकती है। वहीं गुजरात जायंट्स ने 15 खिलाड़ियों को बरकरार रखा है।

टीम ने केवल 4 खिलाड़ियों को रिलीज किया है। इनमें इस साल महिला टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली डैनी वायट-हॉज भी शामिल हैं। उनके अलावा आयुषी सोनी, तितास साधु और शिवानी सिंह को रिलीज किया गया है। गुजरात के पास 1.25 करोड़ रुपये का पर्स है और टीम को 3 खिलाड़ियों की जगह भरनी है। इनमें 1 विदेशी खिलाड़ी के लिए स्थान है।

ब्रैडमैन के इन कीर्तिमानों के आसपास भी नहीं पहुंचा है आधुनिक युग का कोई क्रिकेटर

सिडनी। टेस्ट क्रिकेट में आजकल आक्रामक अंदाज में खेलने का चलन शुरू हो गया है। इसके पीछे तर्क ये है कि इससे विरोधी टीम पर दबाव बनाकर मैच जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी कारण आजकल टेस्ट क्रिकेट में भी कई बल्लेबाज तेज पारियों खेलते दिखते हैं पर इसके बाद भी कोई भी आधुनिक युग का क्रिकेटर महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन के रिकार्ड के आसपास तक भी नहीं पहुंचा है। ब्रैडमैन ने अपने करियर में ऐसे कई असाधारण कीर्तिमान स्थापित किए थे जो कई दशक के बाद भी बने हुए और आगे भी कोई इन रिकार्डों को तोड़ पायेगा। ऐसी उम्मीदें नहीं हैं। ब्रैडमैन ने बल्लेबाजी के ऐसे मानक स्थापित किए,

जिनके आसपास पहुंचना भी आधुनिक दौर के दिग्गज खिलाड़ियों के लिए संभव नजर नहीं आता। इसमें सबसे पहले आता है। ब्रैडमैन का टेस्ट क्रिकेट में 99.94 का बल्लेबाजी औसत। ब्रैडमैन ने अपने 52 टेस्ट मैचों के करियर में असाधारण निरंतरता के साथ रन बनाए। आज के क्रिकेट में 50 से अधिक का औसत भी किसी बल्लेबाज को महान खिलाड़ियों की श्रेणी में पहुंचा देता है पर ब्रैडमैन का औसत इससे लगभग दोगुना रहा। यह एक ऐसा आंकड़ा है जो क्रिकेट के आंकड़ों में अविश्वसनीय माना जाता है। उनके करियर की अंतिम टेस्ट पारी भी यादगार रही, जब औसत 100 तक पहुंचाने के

लिए उन्हें केवल चार रन चाहिए थे, लेकिन ये शून्य पर आउट हो गए। इसके बावजूद, 99.94 का यह औसत आज भी टेस्ट क्रिकेट के सबसे अद्भुत आंकड़ों में शामिल है। वर्ष 1930 की एशेज सीरीज में ब्रैडमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ रन बनाने का एक ऐसा रिकार्ड बनाया जो आज तक बना हुआ है। पांच टेस्ट मैचों की उस सीरीज में उन्होंने कुल 974 रन बनाए। किसी एक टेस्ट सीरीज में यह सर्वाधिक रनों का रिकार्ड है, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता है। इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए ब्रैडमैन को रोकना बेहद मुश्किल साबित हुआ और उनकी बल्लेबाजी उस दौर की सबसे बड़ी कहानी बन गई।

पाटीदार बाहर, शुभम फिर संभालेंगे मध्यप्रदेश की कमान

रणजी ट्रॉफी के लिए 17 सदस्यीय टीम घोषित

इंदौर। नियमित कप्तान रजत पाटीदार की अनुपलब्धता के कारण शुभम शर्मा 2026-27 रणजी ट्रॉफी सत्र में मध्यप्रदेश की कमान संभालेंगे। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एमपीसीए) के सचिव सुधीर असनानी ने 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की। टीम में अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाले आवेश खान और कुलदीप सेन के साथ भारत के लिए टेस्ट पदार्पण कर चुके सारांश जैन को भी शामिल किया गया है।

पाटीदार और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अरशद खान को ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ छह अक्टूबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए इंडिया-ए टीम में चुना गया है। इसके कारण दोनों रणजी ट्रॉफी के शुरूआती मुकाबलों में मध्यप्रदेश के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। शुभम पहले भी मध्यप्रदेश की रणजी टीम की कप्तानी कर चुके हैं। मध्यक्रम के बल्लेबाज शुभम दाएं हाथ से ऑफ स्पिन भी करते हैं। पाटीदार और अरशद की अनुपलब्धता के कारण उन्हें कप्तानी सौंपी गई है।

ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर सर्जरी के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और इस कारण रणजी सत्र में मध्यप्रदेश के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे।

टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण में आवेश खान और कुलदीप सेन शामिल हैं। स्पिन विभाग में कुमार कार्तिकेय और सारांश जैन को जगह मिली है। सारांश ने 23 अगस्त को कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ भारत के लिए टेस्ट पदार्पण



किया था।

बल्लेबाजी में यश दुबे, हर्ष गवली, हिमांशु मंत्री, चंचल राटोर, हिमांशु शिंदे और अथर्व महाजन को शामिल किया गया है। हर्ष गवली और हिमांशु मंत्री विकेटकीपर के विकल्प होंगे।

:: ये है 17 सदस्यीय टीम ::
शुभम शर्मा (कप्तान), हर्ष गवली (विकेटकीपर), यश दुबे, चंचल राटोर, हिमांशु शिंदे, अथर्व महाजन, सारांश जैन, कुमार कार्तिकेय, शिवंग कुमार, आर्यन पुाद, अनुभव अग्रवाल, रोशन केाट, अक्षय शर्मा, आवेश खान, कुलदीप सेन और रवि किरण।

(विकेटकीपर), यश दुबे, चंचल राटोर, हिमांशु शिंदे, अथर्व महाजन, सारांश जैन, कुमार कार्तिकेय, शिवंग कुमार, आर्यन पुाद, अनुभव अग्रवाल, रोशन केाट, अक्षय शर्मा, आवेश खान, कुलदीप सेन और रवि किरण।

मध्यप्रदेश ने जून 2022 में बेंगलुरु में 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था।

यूपीआई लेनदेन की संख्या सितंबर में 23 प्रतिशत बढ़ी, वैल्यू 29 लाख करोड़ रुपए के पार



नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के लेनदेन की संख्या सालाना आधार पर 23 प्रतिशत बढ़कर 24.07 अरब हो गई, वहीं, लेनदेन का कुल मूल्य 18 प्रतिशत बढ़कर 29.37 लाख करोड़ रुपए हो गया।

औसतन सितंबर में यूपीआई के जरिए प्रतिदिन करीब 80.2 करोड़ लेनदेन हुए. इन लेनदेन का औसत दैनिक मूल्य लगभग 97,913 करोड़ रुपए रहा. अगस्त में यूपीआई लेनदेन की संख्या सालाना आधार पर 22 प्रतिशत बढ़कर 24.51 अरब हो गई थी, जबकि लेनदेन का मूल्य 20 प्रतिशत बढ़कर 29.82 लाख करोड़ रुपए रहा था.

एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार, आईएमपीएस के जरिए तत्काल फंड ट्रांसफर की राशि सितंबर में सालाना आधार पर 18 प्रतिशत बढ़कर 7.06 लाख करोड़ रुपए हो गई है. वहीं, इसके जरिए औसतन प्रतिदिन 1.18 करोड़ लेनदेन हुए, जबकि औसत दैनिक लेनदेन राशि 23,530 करोड़ रुपए रही. इसके अतिरिक्त, प्रमुख व्यापारी संगठनों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राष्ट्रीय राजधानी में बैठक के बाद 2 अक्टूबर को हानो यूपीआई डेडलिन माने का अपना आह्वान वापस ले लिया है. विभिन्न राज्यों के करीब 20 व्यापारिक प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री से मुलाकात कर 2,000 रुपए से अधिक के मचैट यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत शुल्क को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कीं. व्यापारियों ने कहा कि इस कदम से छोटे और मध्यम कारोबारों पर बोझ बढ़ सकता है और व्यापारियों के बीच डिजिटल भुगतान को अपनाने पर असर पड़ सकता है. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चांदनी चौक से सांसद और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने किया. एमडीआर केवल 2,000 रुपए से अधिक के पी2एम (व्यक्ति से व्यापारी) लेनदेन पर लागू होता है. 2,000 रुपए तक के लेनदेन पर एमडीआर शून्य बना रहेगा. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2,000 रुपए तक के लेनदेन यूपीआई के मचैट लेनदेन की कुल संख्या के 96 प्रतिशत से अधिक हैं. इसका मतलब है कि यूपीआई भुगतानों की बड़ी संख्या एमडीआर के दायरे में नहीं आएगी और इसलिए एमडीआर पर कोई जीएसटी भी नहीं लगेगा. जिन व्यापारियों की मासिक यूपीआई प्रारितियां 1 लाख रुपए तक हैं, उन्हें एमडीआर का भुगतान नहीं करना होगा. नए यूपीआई ढांचे का व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) लेनदेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. राशि कितनी भी हो, सभी पी2पी लेनदेन के लिए यूपीआई पूरी तरह मुफ्त बना रहेगा.

मुम्बई। मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला. सुबह 9:22 पर सेंसेक्स 160 अंक का 0.22 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 72,319 और निफ्टी 79 अंक या 0.35 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,541 पर था.

शुरूआती कारोबार में सबसे अधिक दबाव ऑटो शेयरों पर देखा जा रहा था. सूचकांकों में निफ्टी ऑटो टॉप लूजर था. इसके बाद निफ्टी कंज्रेशन, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी इन्फ्रा, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी

आईआरएफसी को 396 करोड़ का जीएसटी नोटिस; दूसरी तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2.2%

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) को वित्त वर्ष 2022-23 से जुड़े मामले में बिहार के जीएसटी अधिकारियों से 396.90 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है। इसमें लागू ब्याज और जुमाना भी शामिल है। कंपनी ने कहा, वह नोटिस की जांच कर रही है और टेक्स सलाहकारों की राय के आधार पर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करेगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था अप्रैल से जून तिमाही में 2.2 फीसदी की दर से बढ़ी। उपभोक्ता खर्च और कारोबार निवेश मजबूत रहा। वाणिज्य विभाग ने बुधवार को बताया कि सकल घरेलू उत्पाद की यह वृद्धि जनवरी से मार्च की 2.5 फीसदी दर से कम रही।



इंडिया डिफेंस, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी पीएसई, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी एनर्जी और

निफ्टी पीएसई बैंक लाल निशान में थे. दूसरी निफ्टी आईटी, निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में मजबूती

के साथ कारोबार हो रहा था.

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा था. निफ्टी

जेट फ्यूल की कीमतों में करीब 16 रुपये प्रति लीटर का इजाफा, क्या महंगी होगी हवाई यात्रा ?

नई दिल्ली। अक्टूबर के पहले ही दिन देशवासियों को महंगाई का झटका लग गया. कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के साथ विमानन टरबाइन ईंधन यानी जेट ईंधन की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला. जिससे घरेलू एयरलाइनों की परिचालन लागत पर नया दबाव पड़ रहा है. सरकारी तेल विपणन कंपनी के मुताबिक, एटीएफ की दरों में लगभग 16 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है.

जबकि 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 62.59 रुपये की वृद्धि हुई है. ये बदलाव मासिक संशोधन अंतरराष्ट्रीय मानक कीमतों और रुपये-डॉलर विनिमय दर में बदलाव के बीच किया गया है. बता दें कि एटीएफ एयरलाइनों के लिए एक बड़ा खर्च है और उनकी परिचालन लागत का 40 प्रतिशत तक होता है.

बढ़कर करीब 137 रुपये प्रति लीटर हुई एटीएफ की कीमत

बता दें कि गुरुवार को घरेलू एयरलाइनों के लिए, एटीएफ की कीमतें 121 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर लगभग 137 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं. यह पिछले महीने की तुलना में लगभग 16 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि है. यह नई वृद्धि एटीएफ की कीमतों में लगातार दो बढ़ोतरी के बाद हुई है. इससे पहले सितंबर में, विमानन ईंधन 6.28 रुपये प्रति लीटर था 5.46 प्रतिशत महंगा हो गया था. जबकि अगस्त में इसमें 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी. बता दें कि जेट ईंधन एयरलाइन के परिचालन खर्चों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. इसलिए एटीएफ की कीमतों में लगातार वृद्धि से उड़ानों के संचालन की लागत बढ़ सकती है.



एयरलाइनों पर वास्तविक प्रभाव ईंधन की खपत, मार्ग की लंबाई, बैठे की दक्षता और अन्य परिचालन खर्चों के आधार पर भिन्न हो सकता है. बता दें कि भारत में एयरलाइन के कुल परिचालन व्यय का लगभग 35-40 प्रतिशत हिस्सा एटीएफ (अल्ट्रा-फ्यूल) पर खर्च होता है, जिससे घरेलू एयरलाइनों के लिए जेट ईंधन की

कीमतें एक महत्वपूर्ण लागत बन जाती हैं. एटीएफ की ऊंची कीमतों से एयरलाइनों की परिचालन लागत बढ़ने की आशंका है. ईंधन की ऊंची कीमतों से हवाई किराए में भी वृद्धि हो सकती है. हालांकि, हवाई टिकट की कीमतें यात्रियों की मांग, एयरलाइनों के बीच प्रतिस्पर्धा और सीटों की उपलब्धता जैसी परिस्थितियों पर भी

निर्भर करती हैं. बता दें कि गुरुवार यानी 1 अक्टूबर को एटीएफ के साथ-साथ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली. 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब पिछली बार की तुलना में 62.59 रुपये अधिक होगी. इससे पहले सितंबर में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 9.50 रुपये की मामूली वृद्धि हुई थी. हालांकि उससे पहले कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में लगातार दो महीनों तक भारी गिरावट देखने को मिली थी. अगस्त में, 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 192 रुपये सस्ता हुआ था, जबकि जुलाई में इसकी कीमतों में 183.50 रुपये की कमी दर्ज की गई थी. हालांकि उछाल इस साल की शुरूआत में व्यावसायिक एलपीजी की कीमतों में आई भारी वृद्धि के बाद आए है.

महत्वपूर्ण खबर

सेवा संकल्प यात्रा उज्जैन पहुंची, युवा संवाद में मुख्यमंत्री वर्चुअली जुड़े

■ भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सेवा कार्यों को आगे बढ़ावें। उनके द्वारा किये जा रहे जन-कल्याण के कार्यों को जन-जन तक पहुंचावें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत वाराणसी से वड़मनार तक चल रही सेवा यात्रा के उज्जैन पहुंचने पर विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम को भोपाल से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यात्रा के लिए सेवा यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों से नागरिकों को जोड़े। अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेवा यात्री खान पान, संस्कृति का आपस में आदान प्रदान करें एवं सदभावना के साथ यात्रा को आगे बढ़ावें।

युवाओं को हर हाल में नशे से बचाएं : मुख्यमंत्री

■ भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि युवाओं को हर हाल में नशे से बचाएं। विशेष रूप से शहरों में जो हॉट स्पॉट हैं वहां निगरानी रखी जाए। जिला स्तर पर प्रत्येक माह बैठक होना चाहिए जिसमें नशा मुक्त भारत पर विचार के साथ क्रियान्वयन की दिशा में भी आगे बढ़ा जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में नशा मुक्त भारत के संबंध में वीडियो काफ़िस द्वारा कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की नियमित समीक्षा की जा रही है। प्रदेश में निरंतर समीक्षा के साथ दोषियों के विरुद्ध सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस और आबकारी विभाग आवश्यकतानुसार संयुक्त कार्रवाई में पीछे न हटें।

मंत्री श्री सारंग ने वार्ड 39 में किया पार्क का भूमि-पूजन

■ भोपाल। सहकारिता, खेल और युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने बुधवार को नरेला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 39 स्थित नवीन नगर में नवीन पार्क के निर्माण कार्य का भूमि-पूजन किया।

इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्क के निर्माण से स्थानीय रहवासियों एवं आसपास के नागरिकों को स्वच्छ, हरा-भरा और बेहतर वातावरण उपलब्ध होगा।

'छह महीने में जूनियर वकीलों के स्टाइपेंड की गाइडलाइन तैयार करें', एमपी हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जूनियर अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड दिए जाने को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।

हाई कोर्ट ने मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद से कहा है कि वह छह माह में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के परामर्श से जूनियर अधिवक्ताओं के लिए न्यूनतम स्टाइपेंड तय करने संबंधी गाइडलाइन तैयार करें। हाई कोर्ट ने शहरी क्षेत्र में 20 हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 15 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाने की

सिफारिश की है। दरअसल, कुछ जूनियर अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि नियामक संस्था होने के नाते राज्य अधिवक्ता परिषद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जूनियर अधिवक्ताओं को उनके खर्च और आवागमन के लिए स्टाइपेंड मिले। हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 15 अक्टूबर 2024 के संकुलर का उल्लेख भी किया है।

डिंडौरी में खड़ी कार से टकराई बाइक



डिंडौरी। जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आमचुआ के पास जबलपुर अमरकंटक रोड में बाइक सवार युवक कार से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बाइक सवार सड़क किनारे खड़ी कार के पिछले हिस्से से टकराकर वाहन का कांच तोड़ते हुए अंदर घुस गया। घटना की जानकारी लगते ही डायल 112 स्टाफ मौके पर पहुंचा और गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया।

शाहपुर से लौटते समय हुआ हादसा

घटना के संबंध में थाना प्रभारी शाहपुर केवल सिंह परते ने बताया कि मनोज तेकाम उम्र 30 साल निवासी ग्राम आमचुआ गुरुवार की सुबह मोटरसाइकिल से अपने घर से शाहपुर तक आया था। शाहपुर से वापस लौटते समय सुबह लगभग 8 से 8:30 बजे के बीच सड़क किनारे खड़े वार पहिया वाहन क्रमांक एमपी 20 एक्सबी 1638 के पिछले हिस्से से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक कार का पीछे का कांच तोड़ते हुए अंदर की ओर लटक गया। युवक की मोटरसाइकिल भी हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर राहगीर जमा हो गए और उनके बीच चर्चाओं का शूर हो गया। राहगीरों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई। बताया गया कि युवक बेहोश है और उसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। बताया गया कि हादसे के दौरान चालक कार खड़ी कर पास में ही मौजूद था। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

रामकथा सुनी तो लिखने लगीं किताब, मुस्लिम युवती राहत जहां अब उर्दू-हिंदी में बताएंगी रामचरित मानस की अनुभूति

दतिया। रामकथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि यह प्रेम और मानवता का संदेश देती है। इसी भावना ने दतिया के इंदरगढ़ निवासी मुस्लिम युवती राहत जहां खानम को रामचरित मानस की अनुभूतियों को उर्दू और हिंदी में किताब के रूप में लिखने के लिए प्रेरित किया।

दरअसल, मनोविज्ञान की शोधार्थी और लेखिका राहत ने 15 से 23 सितंबर तक आगरा में आयोजित मोरारी बापू की नौ दिवसीय रामकथा में भाग लिया और अंतिम दिन अपने अनुभवों को एक पत्र के रूप में व्यासपीठ पर मोरारी बापू को सौंपा, तो पंडाल में तालियां गुंज उठीं। राहत के अनुसार इसी प्रसंग में उनका



मन बदल दिया। राहत ने बताया कि कथा के पहले दिन से ही उन्हें आत्मिक आनंद का अनुभव होने लगा। उन्होंने पूरे नौ दिन

रामचरित मानस कथा का श्रवण किया और वहां हुई सकारात्मक अनुभूति से प्रेरित होकर वह अब किताब लिख रही हैं, जिसका नाम कथा एक, राहत अनेक

रामकथा का इतना असर हुआ कि हर रोज पढ़ती हैं चौपाई

रामकथा का इतना गहरा असर हुआ कि राहत अब वेस्टर्न ड्रेस की जगह पारंपरिक पोशाक पहनने लगी हैं। वह रोज आफिस में हनुमान चालीसा और रामचरित मानस की चौपाई पढ़ती हैं ताकि उसे समझकर किताब में उपयोग कर सकें। उनके आफिस में कुरान शरीफ के साथ हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीरें भी लगी हैं, जिनकी वह रोज पूजा करती हैं। राहत का मानना है कि इंसान को अपने जीवन में चारों धर्मों के प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे सभी ग्रंथ मानवता, प्रेम और सद्भाव का संदेश देते हैं।

रखा है। इस पुस्तक में वह रामकथा से जुड़ी अपनी अनुभूतियों को गजलों और उर्दू-हिंदी शब्दावली के माध्यम से प्रस्तुत करेंगी। हाल ही में वह पीतांबर पीठ पर दर्शन करने गई थीं। इससे

गीन एनर्जी कॉरिडोर योजना, स्वच्छ ऊर्जा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम: मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर वरण -111 (जीईसी-111) योजना को मंजूरी प्रदान करने पर आभार माना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में लिया गया यह महत्वपूर्ण निर्णय है। दीर्घकालिक ऊर्जा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे 135 गीगावॉट तक की नवकरणीय ऊर्जा के एकीकरण और पॉवर इवैल्यूएशन के लिए इंटा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत किया जाएगा।

आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उनकी जमानत की अपील करते हुए कहा कि वह पिछले पांच महीनों से जेल में हैं। वहीं, दिवशा के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीबीआई की 600 पन्नों की चार्जशीट में समर्थ और गिरिबाला सिंह पर दिवशा को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एजेंसी ने दहेज की मांग और दहेज

नई दिल्ली, शुक्रवार 02 अक्टूबर 2026 08

जूनियर अधिवक्ताओं को मिलेगी राहत

हाई कोर्ट के इस फैसले से जूनियर अधिवक्ताओं को राहत मिलेगी। सामान्यतः वकालत स्थापित होने में चार से पांच वर्ष लग जाते हैं। ऐसे में अगर जूनियर अधिवक्ताओं के लिए न्यूनतम स्टाइपेंड तय हो जाएगा, जो उन्हें तीन वर्ष तक मिलेगा, तो उन्हें वकालत के क्षेत्र में खुद को स्थापित करने में मदद मिलेगी।

राजेश खंडेलवाल , एडवोकेट

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह संकुलर सिर्फ सिफारिशात्मक प्रकृति का है। कोर्ट ने राज्य अधिवक्ता परिषद और हाई कोर्ट बार एसोसिएशनों को निर्देशित किया है कि वे सभी जूनियर अधिवक्ताओं को उनके वरिष्ठ

अधिवक्ताओं के लिए किए जाने वाले कार्य का स्टाइपेंड दिलाना सुनिश्चित करें, ताकि शुरुआती दौर में जूनियर अधिवक्ता अपने रोजमर्रा के खर्च उठा सकें। कोर्ट ने राज्य अधिवक्ता परिषद से यह जांच करने

के लिए भी कहा है कि याचिकाकर्ता को स्टाइपेंड का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है।

स्वागत योग्य कदम है

यह स्वागत योग्य कदम है। हालांकि जूनियर अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड शासन की ओर से या राज्य अधिवक्ता परिषद की ओर से मिलना चाहिए। जब शासन जूनियर डाक्टरों को स्टाइपेंड दे सकता है तो फिर जूनियर अधिवक्ताओं को देने में क्या दिक्कत हो सकती है।

एडवोकेट मनीष यादव हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष

नई लीडरशिप के साथ बीजेपी का 'मिशन 2028'

66 कमजोर सीटों पर फोकस, भोपाल में एमपी बीजेपी की बड़ी मीटिंग

हमेशा कार्यकर्ता के घर भोजन करता हूं: देब

प्रदेश प्रभारी का दायित्व संभालने के बाद भोपाल प्रवास पर आए बिबल्व कुमार देब ने कहा कि मैं हमेशा कार्यकर्ता के घर भोजन करता हूं। अमित शाह जी भी अध्यक्ष थे, तब बूथ के कार्यकर्ता के घर जाकर खाना खाते थे। वहीं से हमें भी शिक्षा मिली। मुझे अच्छे लगा प्रदेश अध्यक्ष ने मीना जी के घर भोजन का मौका दिया। दरअसल, प्रदेश प्रभारी बिबल्व कुमार देब ने दलित कार्यकर्ता मीना जाटव के घर भोजन किया। उन्होंने कहा कि मेरी मां का नाम भी मीना है, मेरी मां के नाम वाली महिला के घर भोजन कर रहा हूं, आगे सोचो कैसा होगा। मध्य प्रदेश के साथ मेरा आत्मिक संपर्क रहा है, पार्टी ने मौका दिया आभारी हूं। मध्य प्रदेश मजबूत संगठन के रूप में जाना जाता है, मैं और भी ताकत देने का काम करूंगा। प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा ने कहा कि भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा सौभाग्य है मुझे मध्य प्रदेश राज्य भेजा गया है। कार्यकर्ताओं के साथ संगठन के लिए काम करूँगे। कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय भी बनाने का काम करेगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य, आंध्र प्रदेश के प्रभारी अरविंद भदौरिया, राष्ट्रीय संकुल संयोजक विष्णु दत्त शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री फगन सिंह कुलस्ते, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, समातिया उईके, सांसद लता वानखेड़े सहित अन्य नेता मौजूद थे।

बैठक आरंभ होने के कुछ देर बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। गौरतलब है कि डॉ. महेंद्र सिंह पूर्व प्रभारी, पूर्व सह प्रभारी सतीश उपाध्याय का दायित्व बदलने के बाद पहली बार कोर कमेट्री की बैठक हो रही है। प्रदेश भाजपा को लगभग आठ महीने बाद पूर्व संगठन महामंत्री हितानंद के उत्तराधिकारी के रूप में वंशेश्वर तिवारी मिले हैं।

नवाचार और नई कार्ययोजनाओं से बढ़ेगा मत्स्य उत्पादन

भोपाल। मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री नारायण सिंह पवार की अध्यक्षता में मत्स्य महासंघ की कामकाज समिति की 115वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में वर्ष 2027-28 के प्रस्तावित बजट का अनुमोदन किया गया। राज्यमंत्री श्री पवार ने महासंघ के जलाशयों में सहकारी समितियों को सदस्यता देने से पहले उनका प्रीक्षण करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र और वास्तविक समितियों को ही सदस्यता मिल सके।

उज्जैन में शाही मस्जिद का हिस्सा हटाने के दौरान गिरी मीनार



उज्जैन। उज्जैन के छत्री चौक में रास्ता चौड़ा करने के लिए शाही मस्जिद का हिस्सा हटाने के काम के दौरान मीनार एक हिस्सा नीचे आ गिरा। छत पर गिरे मीनार के हिस्से से वह क्षतिग्रस्त हो गई। उज्जैन प्रशासन ने अब इसे ठीक करवाने का काम शुरू कर दिया है। मस्जिद का 6 फीट का हिस्सा हटाय़ा जा रहा है।

चार दिन से मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद को हटाने का काम कर रहे हैं। इसी दौरान मीनार गिरने से मस्जिद की छत को नुकसान पहुंचा है। उज्जैन में सिंहस्थ के लिए गोपाल मंदिर मार्ग से कंठाल तक सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। हादसे में किसी को भी कोई चोट

पशासन ने शुरू किया मरम्मत का काम

नहीं लगी है। सूचना मिलने के बाद प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, वे यहाँ हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

उज्जैन प्रशासन ने अफवाहों पर किया अलर्ट

उज्जैन जिला प्रशासन ने सभी अफवाहों और सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक जानकारी को लेकर अलर्ट किया है। शहर में सभी से शांति बनाए रखने की अपील की गई है।

खंडवा में हत्या के आरोपियों का अवैध कब्जा हटाया

मृतक की बहन ने मजिस्ट्रेट के पैर छूकर जताया आभार



के स्वजन ने आरोपितों के मकान और अवैध कब्जे हटाने तथा आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद ही पोस्टमार्टम कराने की मांग रखी थी।

इस पर सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सिंह और सीएसपी अभिनव बारंगे ने कार्रवाई का लिखित आश्वासन दिया था। इसके बाद पुलिस ने बुधवार शाम

हत्या के तीन आरोपियों संदीप पुत्र अनिल यादव, अमन पुत्र दिन्ना उर्फ साचिन यादव और प्रथमेश पुत्र संजय यादव को गिरफ्तार कर लिया।

गुरुवार सुबह सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सिंह नगर निगम और पुलिस की टीम के साथ भवानी माता क्षेत्र पहुंचे। यहां आरोपित पक्ष से जुड़ी अस्थायी फूल-माला की दुकान को हटाने की कार्रवाई की गई। टीम के साथ बुलडोजर पहुंचते ही क्षेत्र में हलचल बढ़ गई और आसपास के अन्य अतिक्रमणकारियों में भी हड़कण मच गया। कार्रवाई के बाद मृतक के परिवार की महिलाएं सिटी मजिस्ट्रेट के पास

पहुंचीं। मृतक की बहन ने प्रशासन की कार्रवाई के लिए उनके पैरों में झुककर आभार व्यक्त किया। परिवार ने आरोपी पक्ष के अन्य अवैध मकानों और कब्जों पर भी कार्रवाई की मांग रखी। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने परिवार को धैर्य रखने की बात कही और नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया। विदित हो कि चार दिन पूर्व पारिवारिक व व्यवसायिक रंजिश के चलते किशन गुप्ता और विजय तथा दिन्ना यादव गुट में विवाद हो गया था। दोनों पक्षों के दो-दो लोग गंभीर घायल हुए थे। पुलिस ने दोनों पक्षों पर प्रकरण दर्ज किया था। इस बीच उपचार के दौरान किशन गुप्ता की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

दिवशा शर्मा सुसाइड: रिटायर्ड जज से सीबीआई ने हटाया दहेज उत्पीड़न का आरोप

भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिवशा शर्मा आत्महत्या मामले की आरोपी रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज के लिए परेशान करने का आरोप हटा लिया है। गिरिबाला सिंह के वकील ने बुधवार को हाईकोर्ट को यह जानकारी दी, साथ ही अपनी मुवक्किल के लिए जमानत अर्जी भी दाखिल की। गिरिबाला सिंह अपने बेटे और दिवशा के पति

समर्थ सिंह के साथ फिलहाल जेल में हैं। इस नई जानकारी के बाद, हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह के वकील को जमानत की संशोधित अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 अक्टूबर की तारीख तय की है। वकील सुरेंद्र सिंह ने कोर्ट को बताया कि 14 अगस्त को दाखिल चार्जशीट में सीबीआई ने गिरिबाला सिंह पर दहेज से जुड़े कोई आरोप नहीं लगाए हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि गिरिबाला और समर्थ

सिंह ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 (पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा क्रूरता और उत्पीड़न), 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 3(5) (साझा इरादा) के तहत अपराध किए हैं। हालांकि, सीबीआई को दहेज के लिए उत्पीड़न से जुड़ा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। मूल जमानत अर्जी में इस बात का जिक्र नहीं था कि सीबीआई ने उन पर दहेज से जुड़े आरोप नहीं लगाए हैं, जिसके चलते हाईकोर्ट ने संशोधित अर्जी



दाखिल करने को कहा।

गिरिबाला के वकील ने

के कारण मौत के दावों की जांच अभी खुली रहती है। श्रीवास्तव के अनुसार, जांच अभी जारी है और आरोपियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप से मिले डिजिटल सबूतों की फोरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट का इंतजार है। मॉडल दिवशा शर्मा ने अपने पति समर्थ सिंह से शादी के पांच महीने बाद, 12 मई 2024 को आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने उनकी सास गिरिबाला और पति समर्थ के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज निषेध

कानून के तहत मामला दर्ज किया था। शुरू में, गिरिबाला सिंह को 15 मई को भोपाल जिला और सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 27 मई को उनकी यह जमानत रद्द कर दी थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में मृतका का दोबारा पोस्टमार्टम दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की टीम से करवाने का भी आदेश दिया था। राज्य सरकार ने बाद में इस संवेदनशील मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।